अध्याय V

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियां

शहरी सहकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है। वर्ष 2011-2012 में, इस क्षेत्र में आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई तथा अनर्जक आस्तियों के अनुपात में और भी कमी हुई। नए कैमेल्स रेटिंग मॉडल के अनुसार शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा 61 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के पास है जिनकी रेटिंग 'ए' तथा बीट रही जो इस क्षेत्र की अच्छी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को देखा जाए तो 2010-11 में राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ और सुधार की आंशिक वजह विवेकपूर्ण विनियामक सुधार और अल्पावधि ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के लिए पुनरूज्जीवन पैकेज का लागू किया जाना रहे। तथापि दीर्घावधि ऋण देने वाली ग्रामीण सहकारी संस्थाओं जैसे राज्य और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर रही। इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए, यह आवश्यक है कि पुनर्पूंजीकरण और विनियामक सुधारों को जारी रखा जाए ताकि वित्तीय समावेशन और कृषि में ग्रामीण सहकारी क्षेत्र से ऋण सहायता मिल सके।

1. भूमिका

5.1 बैंकों के प्रभुत्व वाली भारतीय वित्तीय प्रणाली में सहकारी संस्थाओं का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है; तथापि भौगोलिक तथा जनसांख्यिकीय दृष्टि से उनकी पहुंच को देखते हुए, वित्तीय प्रणाली में उनका प्रमुख स्थान है।[1] भौगोलिक रूप से देखा जाए तो सहकारी समितियां भारत के गावों और छोटे कस्बों में औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सहायक रही हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टि से देखा जाए तो इन संस्थाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निम्न और मध्य आय वर्ग वाले लोगों तक वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को सुकर बनाया है।

5.2 वित्तीय प्रणाली में समावेशन बढ़ाने में उनकी भूमिका के बावजूद, ये संस्थाएं कमजोर वित्तीय स्थिति की वजह से खराब हालत में हैं जिनका आंशिक कारण परिचालन और गवर्नेंस से जुड़ी परेशानियां रही हैं। इसलिए इन संस्थाओं में नई जान फूंकने के लिए कई विकासात्मक तथा विनियामक उपाय किए जा रहे हैं। शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में रिज़र्व बैंक ने अपने विज़न दस्तावेज 2005 के क्रम में, अधिक एकीकृत विनियामक ढांचे को अपनाया है जिसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को समेकित और मजबूत बनाना है। यदि अल्पावधि ऋण देने वाली ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की बात की जाए तो विवेकपूर्ण विनियमन अपनाए जाने और उसके बाद उनके पुनर्पूंजीकरण से इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्तमान में किए जा रहे इन प्रयासों के अलावा, 2011-12 में सहकारी क्षेत्र में बहुत से नए नीतिगत उपाय किए गए हैं जिनका वर्णन अध्याय 3 में किया गया है।

5.3 इस अध्याय में इन नीतिगत प्रयासों के आलोक में 2011-12 में सहकारी संस्थाओं के निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। साथ ही इस विश्लेषण में जहां आवश्यक है वहां वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों की तुलना में समय-क्रम तथा विभिन्न अंशों की आपसी तुलना प्रस्तुत की गई है। चूंकि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित आंकड़े एक वर्ष के अंतराल पर ही उपलब्ध हो पाते हैं, इसलिए इन संस्थाओं का विश्लेषण वर्ष 2010-11 तक के लिए ही संभव हो पाया है। इस अध्याय में शामिल विश्लेषण समग्ररूप से 1,618 शहरी सहकारी बैंकों और 94,531 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित है जिसमें चार्ट V.1 में दी गई अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाएं शामिल हैं।

[1] मार्च 2011 के अंत में ग्रामीण और शहरी सहकारी संस्थाओं को मिलाकर उनकी आस्ति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित कुल आस्ति का लगभग 12 प्रतिशत रही।

चार्ट V.1: भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं का ढांचा

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

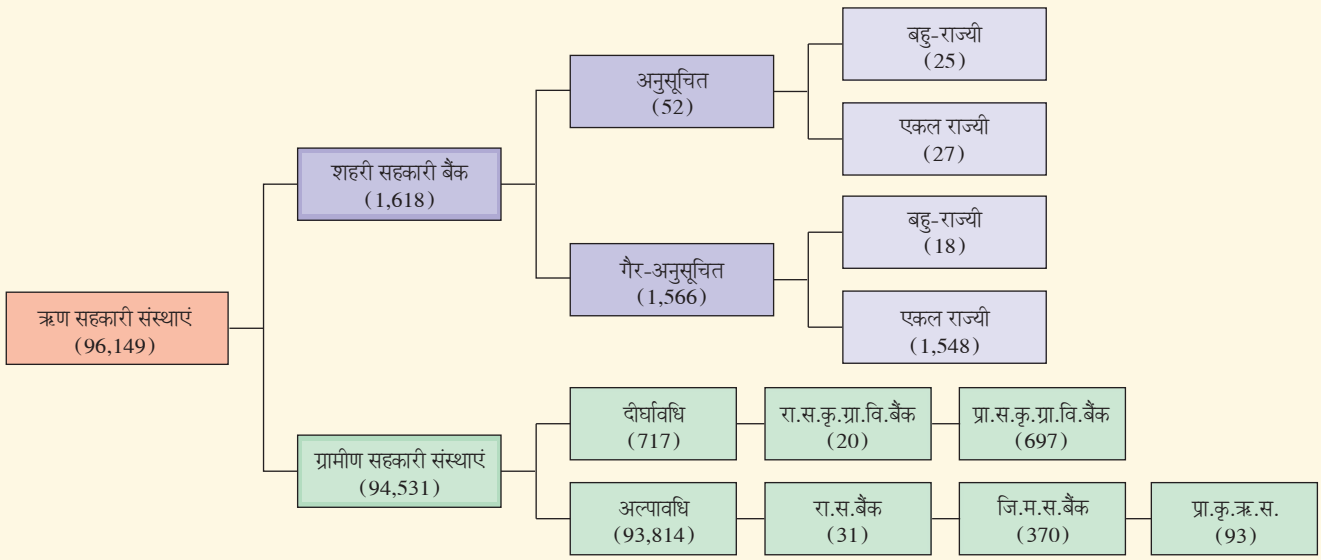

रा.स.बैंक : राज्य सहकारी बैंक; जि.म.स.बैंक: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; प्रा.कृ.ऋ.स: प्राथमिक कृषि ऋण समिति; रा.स.कृ.ग्रा.वि.बैंक: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; प्रा.स.कृ.ग्रा.वि.बैंक : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मार्च 2012 के अंत में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में संस्थाओं की संख्या और मार्च 2011 के अंत में ग्राणीण सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं।
2. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के संबंध में सहकारी संस्थाओं की संख्या, रिपोर्टिंग करने वाली सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाती है।

5.4 इस अध्याय को छह खंडों में बांटा गया है। खंड 2 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों एवं देयताओं, आय एवं व्यय तथा सुदृढ़ीकरण के संकेतकों का इस्तेमाल कर उनके निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। खंड 3 में अल्पावधि तथा दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के विभिन्न टियरों (स्तरों) के निष्पादन की समीक्षा की गई है। खंड 4 एवं 5 में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की लाइसेंसिंग और इन संस्थाओं को दिए जाने वाले पुनरुज्जीवन पैकेज से संबंधित महत्त्वपूर्ण गतिविधियों की चर्चा की गई है। खंड 6 में किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गतिविधियों का वर्णन किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण ऋण से जुड़ी एक योजना है जिसमें ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को शामिल किया गया है। खंड 7 में इस अध्याय की प्रमुख बातों का सार प्रस्तुत किया गया है।

2. शहरी सहकारी बैंक

समेकन के जरिए अपेक्षाकृत मजबूत शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र का उद्भव

5.5 रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के पुनरुज्जीवन के लिए वर्ष 2005 में विज़न दस्तावेज प्रस्तुत किया, तब से यह क्षेत्र वित्तीय रूप से मजबूत हुआ है। इस दस्तावेज में रिज़र्व बैंक ने बहुस्तरीय विनियामक और पर्यवेक्षी पद्धति निर्धारित की है। यह पद्धति अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के विलय/समामेलन और गैर-अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के समाप्त होने पर केंद्रित है। समेकन की इस प्रक्रिया की वजह से शहरी सहकारी बैंकों की संख्या लगातार कम हो रही है (चार्ट V.2)। यह प्रवृत्ति जारी रहने के कारण शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या मार्च के 2011 अंत में 1,645 थी जो मार्च 2012 के अंत में 1,618 रह गई। इसके अलावा 2005 से 2011 के बीच वित्तीय दृष्टि से मजबूत शहरी सहकारी बैंकों (ग्रेड I एवं II के रूप में परिभाषित शहरी सहकारी बैंक) की संख्या नियमित रूप से बढ़ी है और वित्तीय दृष्टि से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों (ग्रेड III एवं IV के रूप में परिभाषित शहरी सहकारी बैंक) की संख्या कम हुई है[2]।

5.6 महाराष्ट्र, जहां शहरी सहकारी बैंकों की संख्या सबसे अधिक है, में सर्वाधिक विलय हुए। 2005 से मार्च 2012 के अंत

[2] शहरी सहकारी बैंकों के ग्रेड आधारित वर्गीकरण के आंकड़े वर्ष 2012 के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस प्रकार का वर्गीकरण बंद कर दिया गया है और शहरी सहकारी बैंकों का एक नई रेटिंग आधारित वर्गीकरण शुरू किया गया (इस अध्याय के अंत में विवरण दिया गया है)। शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय निष्पादन के आधार पर ग्रेड तय किये जाते थे जिनमें पूंजी पर्याप्तता, अनर्जक आस्तियों का स्तर और लाभ/हानि का इतिहास जैसे मानक शामिल थे।

चार्ट V.2: वित्तीय क्षमता के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों की संख्या और संरचना

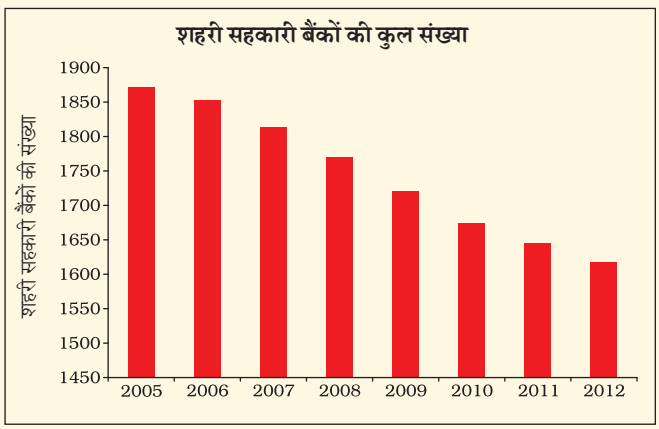

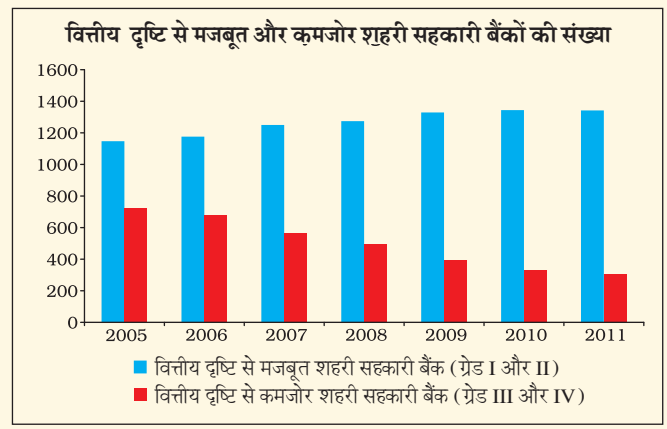

तक कुल जितने भी विलय हुए उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा 61 प्रतिशत था जिसके बाद 19 प्रतिशत हिस्से के साथ गुजरात और 8 प्रतिशत हिस्से के साथ आंध्र प्रदेश का क्रम आता है (चार्ट V.3)

चार्ट V.3: मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में हुए समेकन की प्रगति

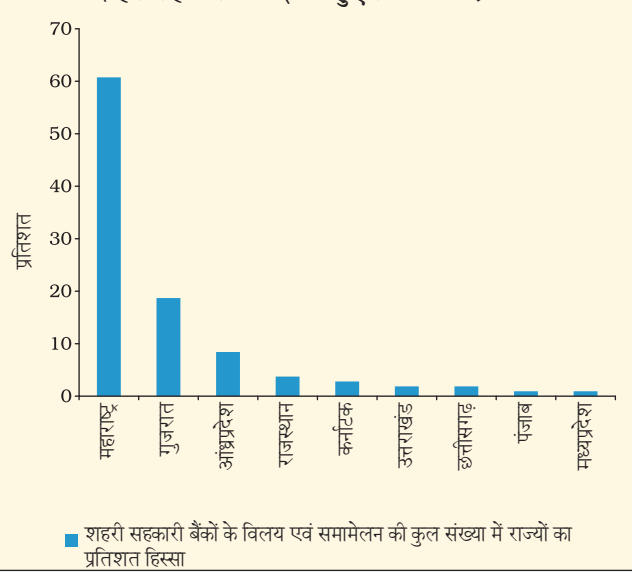

वर्ष 2011-12 में टियर।। शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में तेज वृद्धि शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में हुए विस्तार को प्रतिबिंबित करती है

5.7 2005 के विज़न दस्तावेज के अनुसरण में शहरी सहकारी बैंकों को उनकी जमाराशि के आधार पर टियर । और टियर ।। श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और इन दोनों श्रेणियों[3] के लिए अलग-अलग विनियामक अपेक्षाएं तय की गईं। हाल के वर्षों में, ऐसे टियर ।। बैंक जिनका जमाराशि आधार बड़ा है और जो भौगोलिक रूप से अधिक स्थानों पर फैले हुए हैं, वे संख्या और आस्ति के आकार की दृष्टि से बढ़ गए हैं। (सारणी V.1 और चार्ट V.4)

शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय मजबूती का आकलन करने के लिए नई कैमेल्स रेटिंग

5.8 शहरी सहकारी बैंकों को विनियामक और पर्यवेक्षी प्रयोजन से पहले उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। कैमेल्स (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि और प्रणालियां एवं नियंत्रण) रेटिंग मॉडल की शुरुआत के साथ, इस प्रकार के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया

[3] ऐसे शहरी सहकारी बैंकों को टियर I शहरी सहकारी बैंकों के रूप में परिभाषित किया गया जो:

- 1 बिलियन रुपये से कम जमाराशि के साथ एक ही जिले में कार्य करते हों।
- 1 बिलियन रुपये से अधिक जमाराशि के साथ एक से अधिक जिले में कार्य करते हों बशर्ते शाखाएं समीपवर्ती जिले में हों और बैंक की कुल जमा तथा अग्रिम में एक अकेले जिले की जमा का अलग से कम-से-कम 95 प्रतिशत हिस्सा हो।
- 1 बिलियन रुपये से कम जमाराशि आधार हो और जिसकी शाखाएं मूल रूप से एक ही जिले में हों लेकिन जिले के पुनर्गठन के कारण वे बाद में बहु-जिलाक्षेत्र वाले बन गए हों।

अन्य सभी शहरी सहकारी बैंक टियर II शहरी सहकारी बैंक के रूप में परिभाषित किए गए हैं।

सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

टियर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमा		अग्रिम		आस्ति	
	संख्या	कुल की तुलना में प्रतिशत	संख्या	कुल की तुलना में प्रतिशत	संख्या	कुल की तुलना में प्रतिशत	संख्या	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
टियर । शहरी सहकारी बैंक	1,234	76.3	410	17.2	260	16.5	527	17.4
टियर ।। शहरी सहकारी बैंक	384	23.7	1,975	82.8	1,320	83.5	2,506	82.6
सभी शहरी सहकारी बैंक	**1,618**	**100.0**	**2,385**	**100.0**	**1,580**	**100.0**	**3,033**	**100.0**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

गया और शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए क्रेडिट रेटिंग आधारित नई प्रणाली प्रारंभ की गई है।

5.9 नए कैमेल्स रेटिंग मॉडल के तहत, बैंकों को कैमेल्स के अलग-अलग घटकों की भारित औसत रेटिंग के आधार पर संयुक्त रेटिंग ए/बी/सी/डी (कार्यनिष्पादन के अवरोही क्रम में) दी जा रही है। जब कभी आवश्यक हो, घटकों के छोटे-छोटे खंडों को दर्शाने और बैंक की संयुक्त रेटिंग को दर्शाने के लिए ए/बी/सी रेटिंग के साथ '+' या '-' चिह्न जोड़ दिया जाता है। 'डी' सबसे कम रेटिंग को दर्शाता है।

5.10 नए वर्गीकरण के अनुसार, मार्च 2012 के अंत में 61 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों की संयुक्त रेटिंग ए और बी थी और शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार (जमा तथा ऋण मिलाकर) में इनका हिस्सा लगभग 78 प्रतिशत था। इसके अलावा, 32 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों की संयुक्त रेटिंग 'सी' थी और शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार में ऐसे शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत था। केवल 7 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों की रेटिंग सबसे कम अर्थात 'डी' रेटिंग थी जो सबसे कमजोर वित्तीय स्थिति का द्योतक है। (सारणी V.2)

सारणी V.2: रेटिंग के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

रेटिंग	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	कुल संख्या में प्रतिशत	जमाराशि	कुल जमाराशि में प्रतिशत	अग्रिम	कुल अग्रिम में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
ए+	5	0.3	36	1.5	27	1.7
ए	46	2.8	366	15.3	251	15.9
ए-	140	8.7	388	16.3	263	16.6
बी+	296	18.3	491	20.6	332	21.0
बी	353	21.8	432	18.1	284	18.0
बी-	141	8.7	148	6.2	93	5.9
सी+	318	19.7	303	12.7	193	12.2
सी	145	9.0	79	3.3	49	3.1
सी-	59	3.6	52	2.2	32	2.0
डी	115	7.1	91	3.8	56	3.6
कुल	**1,618**	**100.0**	**2,385**	**100.0**	**1,580**	**100.0**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट V.4: शहरी सहकारी बैंकों की टियर-वार संरचना

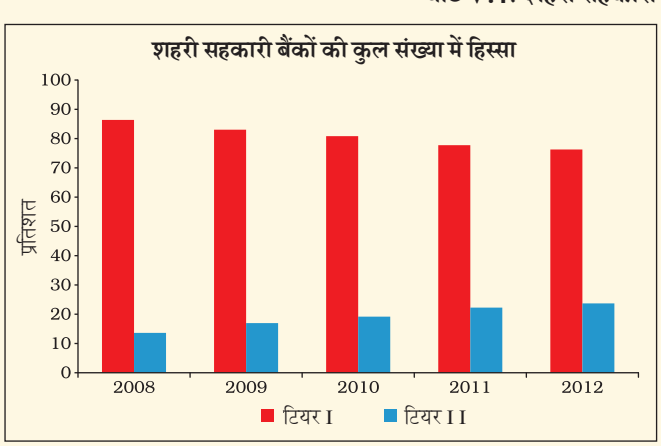

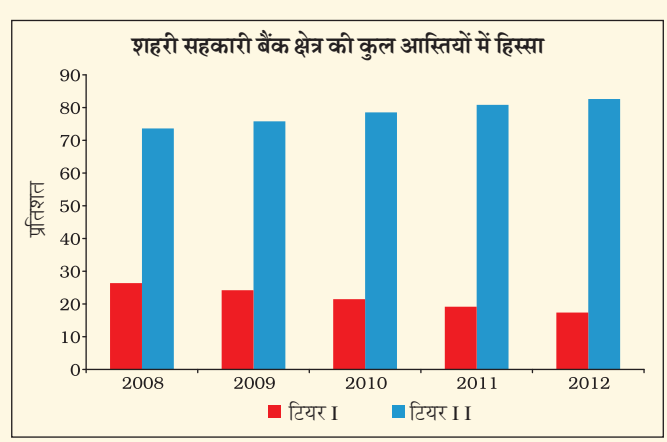

सारणी V.3: जमा एवं अग्रिम के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

जमाराशि (बिलियन रुपये)	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या		जमाराशि की संख्या		अग्रिम (बिलियन रुपये)	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या		अग्रिम की राशि	
	संख्या	प्रतिशत हिस्सा	राशि	प्रतिशत हिस्सा		संख्या	प्रतिशत हिस्सा	राशि	प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 0.10	258	15.9	17	0.7	0 - 0.10	459	28.4	29	1.8
0.10 - 0.25	392	24.2	72	3.0	0.10 - 0.25	450	27.8	75	4.8
0.25 - 0.50	324	20.0	122	5.1	0.25 - 0.50	256	15.8	93	5.9
0.50 - 1.0	300	18.5	321	13.5	0.50 - 1.0	199	12.3	146	9.2
1.0 - 2.5	205	12.7	314	13.2	1.0 - 2.5	149	9.2	256	16.2
2.5 - 5.0	60	3.7	194	8.1	2.5 - 5.0	50	3.1	177	11.2
5.0 - 10.0	40	2.5	264	11.1	5.0 - 10.0	34	2.1	227	14.4
10.0 और अधिक	39	2.4	1,081	45.3	10.0 और अधिक	20	1.2	577	36.5
कुल	**1,618**	**100.0**	**2,385**	**100.0**	**कुल**	**1,618**	**100.0**	**1,580**	**100.0**

2011-12 में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की आस्ति के संकेंद्रण में वृद्धि हुई

5.11 विगत वर्षों में, शहरी सहकारी बैंकों के समेकन में कमी के परिणामस्वरूप शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में आस्ति के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। 2008 और 2012 के बीच 10 बिलियन रुपयों से अधिक आस्ति आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या चौगुनी हो गई। उल्लेखनीय यह है कि इस अवधि के दौरान शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में ऐसे शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग 37 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.5)।

5.12 मार्च 2012 के अंत में, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल जमाराशि में 10 बिलियन रुपयों से अधिक के आधार वाले शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा 45 प्रतिशत था। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के कुल अग्रिम में 10 बिलियन रुपयों से अधिक ऋण आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग 37 प्रतिशत था (सारणी V.3)। बॉक्स V.1 में बाजार संकेंद्रण के विभिन्न सांख्यिकीय मापदंडों का उपयोग करते हुए शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में संकेंद्रण पर विस्तृत चर्चा की गई है।

वर्ष 2011-12 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में कम वृद्धि हो रही है

5.13 वर्ष 2005 में सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद से शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की वृद्धि में काफी तेजी आई और यह एक अंक से बढ़कर द्विअंकीय हो गई। तथापि, 2009-10 में 18 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद वृद्धि लगातार धीमी होती रही, परंतु यह दो अंकों में बनी रही (चार्ट- V.6)।

5.14 2011-12 में ऋण वृद्धि में नरमी आई जो संभवतः वर्ष के दौरान अधिकतर समय ब्याज दरें ऊंची बनी रहने और ऋण मांग कम रहने की सूचक है। एसएलआर निवेशों (सारणी V.4 और V.5) की वृद्धि में आई कमी के कारण 2011-12 में निवेश में भी वृद्धि धीमी रही जबकि शहरी सहकारी बैंकों की निधियों का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग निवेश के लिए होता है।

चार्ट V.5: आस्ति के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

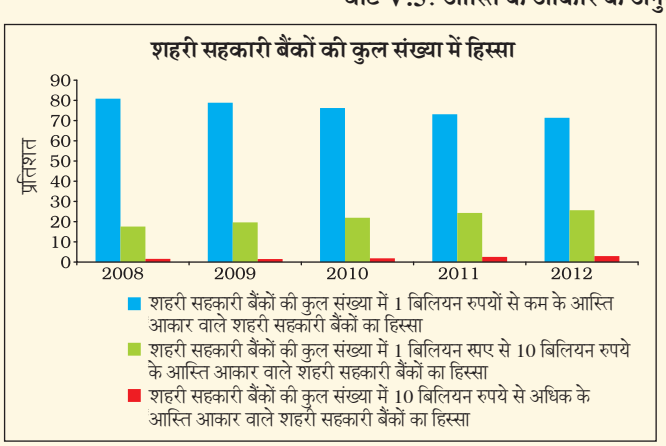

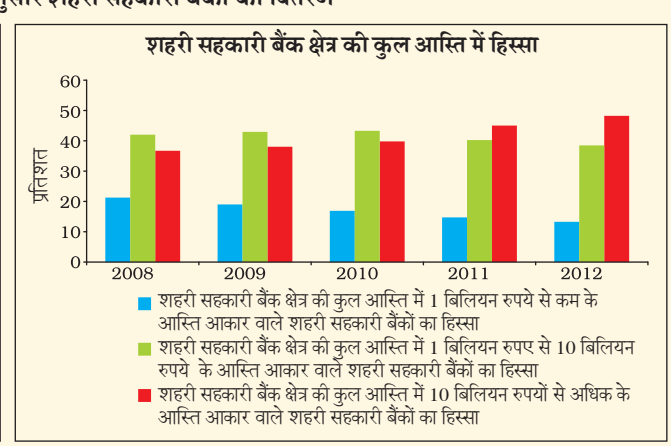

बॉक्स V.1 शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के भीतर बाजार संकेंद्रण का एक विश्लेषण

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के समेकन से संबंधित विज़न दस्तावेज के तैयार किए जाने और मार्गदर्शन के जारी होने के बाद से इस क्षेत्र में असाधारण वृद्धि हुई। 2005 से 2012 के बीच लगभग 13 प्रतिशत की कई गुना अधिक वार्षिक वृद्धि के साथ मार्च 2012 के अंत तक इनका हिस्सा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत हो गया।

चूंकि यह क्षेत्र समेकित हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र के भीतर संकेंद्रण के स्तर में वृद्धि हुई है। यद्यपि बाजार संकेंद्रण का विश्लेषण बहुत सारे सांख्यिकी मापदंडों का उपयोग कर किया जाता है, तथापि शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों की उपलब्धता के मद्देनजर यहां कुछ मापदंडों का चयन किया गया है। उपयोग में लाए गए दो मापदंड निम्नलिखित हैं:

(क) सर्वोच्च चार/आठ/दस बाजार संस्थाओं की हिस्सेदारी (सीआर$_4$/सीआर$_8$/ सीआर$_{10}$) जिसे निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया गया है:

$$CR_k = \sum k_{i=1} S_i$$

जहां S_i संस्था 'आई' की हिस्सेदारी दर्शाता है,

k : अग्रणी 'k' संस्थाओं की संख्या दर्शाता है

यद्यपि यह मापदंड अपेक्षाकृत सरल है, तब भी किसी बाजार के अंतर्गत यह संस्थाओं की कुल संख्या से प्रभावित होता है (बिकर एंड हाफ, 2000)। इस मापदंड के अनुसार, किसी क्षेत्र को तब उच्च संकेंद्रित माना जाता है जब सीआर$_4$ 50 प्रतिशत के से अधिक हो और सीआर$_8$ 75 प्रतिशत से अधिक हो।

इस मापदंड के अनुसार, यह कहा जा सकता है कि 2012 में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में संकेंद्रण कम था और हाल की अवधि में संकेंद्रण के स्तर में वृद्धि हुई। (सारणी 1)

(ख) लॉरेंज वक्र और संबंधित संकेंद्रण गुणांक को (एल आर) ऐसे वक्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो संस्थाओं की संख्या का संचयी वितरण और तदुनसार यह बाजार में उनकी हिस्सेदारी दर्शाता है। संकेंद्रण गुणांक की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है:

संकेंद्रण गुणांक = $1 - \sum(X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k)$

जहां k, 0 से शुरू होकर n-1 पर समाप्त होता है।

x संस्थाओं का संचयी अनुपात दर्शाता है

Y बाजार हिस्सेदारी का संचयी अनुपात दर्शाता है।

सारणी:1 शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में सर्वोच्च चार/आठ/दस शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)

मापदंड	2011	2012
सीआर$_4$	17.8	19.4
सीआर$_8$	23.9	26.2
सीआर$_{10}$	26.4	28.7

चार्ट 1: शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए संकेंद्रण वक्र

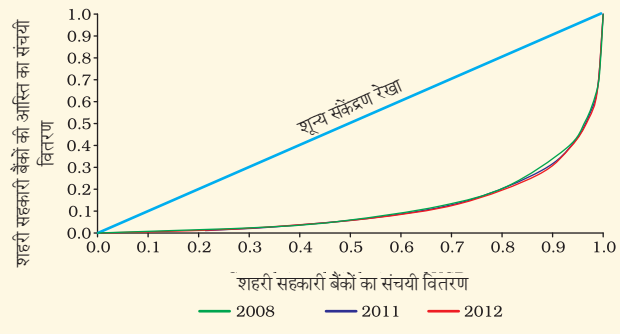

यह गुणांक 0 और 1 के बीच होता है तथा 0 बिल्कुल बराबर हिस्सेदारी को दर्शाता है और 1 पूर्ण एकाधिकार को दर्शाता है। इस मापदंड पर संस्थाओं की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है (पूर्वोक्त)।

चूंकि शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए यह संकेंद्रण गुणांक 0.5 से अधिक था इसलिए इस मापदंड के अनुसार इस क्षेत्र में संकेंद्रण का स्तर अपेक्षाकृत काफी अधिक है। इसके अलावा संकेंद्रण वक्र और संकेंद्रण गुणांक से पता चलता है कि कुछ समय से संकेंद्रण के स्तर में थोड़ी वृद्धि हुई है (चार्ट 1 और सारणी 2)।

अंत में, निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र को समेकित करने पर केंद्रित शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में किए गए विनियामक सुधारों के कारण कुछ हद तक इस क्षेत्र के आस्ति संकेंद्रण स्तर में कहीं कम तो कहीं अधिक वृद्धि हुई है।

सारणी 2: शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के संकेंद्रण गुणांक

वर्ष	संकेंद्रण गुणांक
2008	0.748
2011	0.757
2012	0.761

टिप्पणी: सहगुणांक की गणना शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में से शहरी सहकारी बैंक की हिस्सेदारी के आधार पर की गई है।

संदर्भ:

जे.ए. बिक्कर और के. हाफ (2000), ठमेजर्स ऑफ कांपिटिशन एंड कंसंट्रेशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री: ए रिव्यू ऑफ लिटरेचरड, दे नीदरलैंड बैंक, रिसर्च सीरीज सुपरविज़न नं.27।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी में हो रही वृद्धि शहरी सहकारी बैंकों के पूंजी आधार में विस्तार के रुझान की ओर संकेत करती है

5.15 हाल के वर्षों में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी में वृद्धि का रुझान रहा है जो शहरी सहकारी बैंकों के पूंजीगत आधार में होने वाले विस्तार के सामान्य रुझान की ओर संकेत करता है (चार्ट V.7)। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक वे बैंक हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं तथा जिनकी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियां 0.5 मिलियन रुपयों से कम नहीं है और वे भारतीय रिज़र्व

चार्ट V.6: शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में वृद्धि

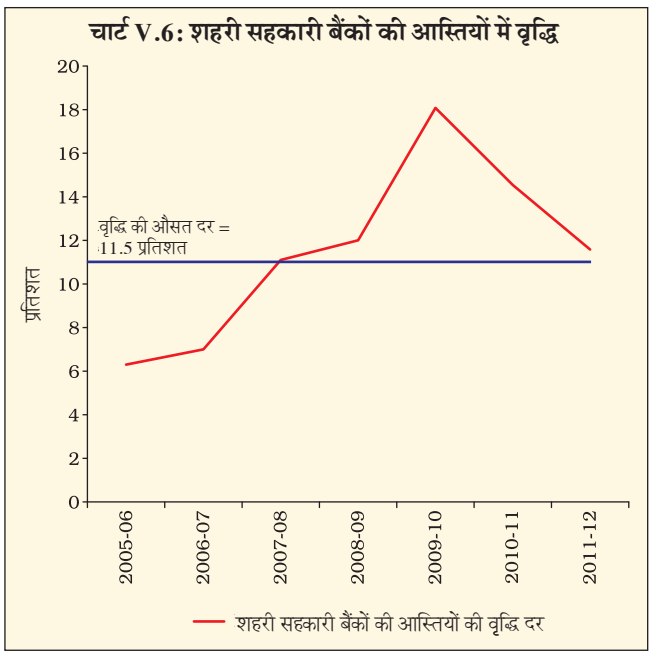

बैंक की संतुष्टि के अनुरूप जमाकर्ताओं के हित में अपना कारोबार करते हों।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात का निरंतर कम स्तर

5.16 यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि का रुझान है जो इन संस्थाओं के बैंकिंग व्यापार में होने वाली सामान्य वृद्धि की ओर संकेत करता है, परंतु यह अनुपात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अनुपात से लगातार कम रहा है (चार्ट V.8)। तदनुरूप, निधियों के प्रयोग के मामले में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों ने निवेश को प्राथमिकता दी।

कुल आय में उच्च वृद्धि के कारण शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार

5.17 2011-12 में शहरी सहकारी बैंकों की समग्र लाभप्रदता के समग्र स्तर में सुधार हुआ जिसका मुख्य कारण इन संस्थाओं की कुल आय में होने वाली लगभग दोगुनी वृद्धि है। (सारणी V.6)। ऋण और ऋण से इतर -दोनों ही घटकों से आय में हुए विस्तार के कारण यह वृद्धि हुई।

सारणी V.4: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(मार्च के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

आस्ति/ देयता	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक		वृद्धि की दर (%) सभी शहरी सहकारी बैंक
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
देयताएं							
1. पूंजी	19 (1.6)	23 (1.6)	44 (2.9)	50 (3.1)	63 (2.3)	73 (2.4)	16.1
2. आरक्षित निधि	112 (9.3)	126 (8.9)	151 (9.9)	143 (8.9)	263 (9.7)	270 (8.9)	2.7
3. जमाराशि	923 (77.1)	1,104 (77.4)	1,195 (78.7)	1,281 (79.8)	2,119 (78.0)	2,385 (78.6)	12.6
4. लिए गए उधार	28 (2.3)	21 (1.5)	16 (1.1)	15 (0.9)	44 (1.6)	36 (1.2)	-18.7
5. अन्य देयताएं	116 (9.7)	152 (10.7)	113 (7.4)	117 (7.3)	230 (8.4)	269 (8.9)	17.3
आस्तियां							
1. नकदी	6 (0.5)	8 (0.5)	17 (1.1)	22 (1.4)	24 (0.9)	30 (1.0)	26.1
2. बैंकों के पास शेष	110 (9.1)	122 (8.6)	133 (8.7)	141 (8.8)	242 (8.9)	263 (8.7)	8.7
3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	6 (0.5)	9 (0.6)	5 (0.4)	7 (0.4)	11 (0.4)	16 (0.5)	44.5
4. निवेश	335 (27.9)	369 (25.9)	516 (33.9)	511 (31.8)	850 (31.3)	880 (29.0)	3.5
5. ऋण और अग्रिम	617 (51.5)	744 (52.1)	748 (49.2)	836 (52.1)	1,365 (50.2)	1,580 (52.1)	15.8
6. अन्य आस्तियां	125 (10.4)	175 (12.3)	101 (6.7)	89 (5.5)	226 (8.3)	264 (8.7)	16.8
कुल देयताएं/ आस्तियां	**1,198 (100.0)**	**1,427 (100.0)**	**1,519 (100.0)**	**1,606 (100.0)**	**2,718 (100.0)**	**3,033 (100.0)**	**11.6**

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित करने के कारण अंतर के प्रतिशत में कुछ परिवर्तन आ सकता है।
3. पूर्णांकित करने के कारण घटकों से प्राप्त जोड़ अलग हो सकता है।

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत अंतर	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
कुल निवेश (क+ख)	**850 (100.0)**	**880 (100.0)**	**7.4**	**3.5**
क. एसएलआर निवेश (i से vi)	**785 (92.3)**	**814 (92.5)**	**10.7**	**3.8**
i) केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियां	513 (60.4)	564 (64.1)	25.7	10.0
ii) राज्य सरकारी प्रतिभूतियां	93 (10.9)	108 (12.3)	18.8	17.2
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	5 (0.6)	3 (0.4)	29.4	-38.4
iv) राज्य सहकारी बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	53 (6.2)	42 (4.8)	-16.6	-20.8
v) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पास मीयादी जमाराशि	107 (12.6)	76 (8.6)	-22.9	-28.9
vi) अन्य, यदि कोई हों	14 (1.7)	21 (2.3)	-18.3	44.7
ख. गैर-एसएलआर निवेश	**65.5 (7.7)**	**65.7 (7.5)**	**-20.5**	**0.4**

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2. निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित करने के कारण अंतर के प्रतिशत में कुछ परिवर्तन आ सकता है।
3. पूर्णांकित करने के कारण घटकों से प्राप्त जोड़ अलग हो सकता है।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाभप्रदता के विविध संकेतकों में वृद्धि का रुझान

5.18 पिछले रुझानों को जारी रखते हुए 2011-12 में शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता के प्रमुख संकेतकों में सुधार जारी रहा (सारणी V.7)। वर्ष के दौरान आस्तियों के प्रतिफल (जो आस्तियों

चार्ट V.7 : शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी

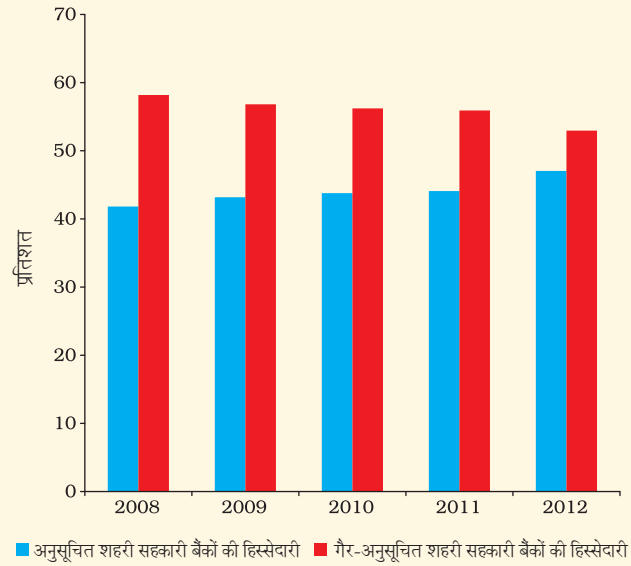

के औसत की तुलना में निवल लाभ का प्रतिशत है) के साथ ही इक्विटी के प्रतिफल (जो इक्विटियों के औसत की तुलना में निवल लाभ का प्रतिशत है) -दोनों में अच्छी वृद्धि हुई।

5.19 इसके अलवा, आस्तियों के प्रतिफल में वृद्धि केवल समग्र या प्रणाली स्तर पर ही नहीं हुई बल्कि अलग-अलग स्तर पर भी वृद्धि हुई। 2011-12 में सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों के प्रतिफल में काफी वृद्धि हुई। इस वर्ष किसी भी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक ने आस्तियों के प्रतिफल ऋणात्मक होने की रिपोर्ट नहीं दी, जैसाकि पिछले वर्षों में होता था (परिशिष्ट सारणी V.1)।

चार्ट V. 8: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात

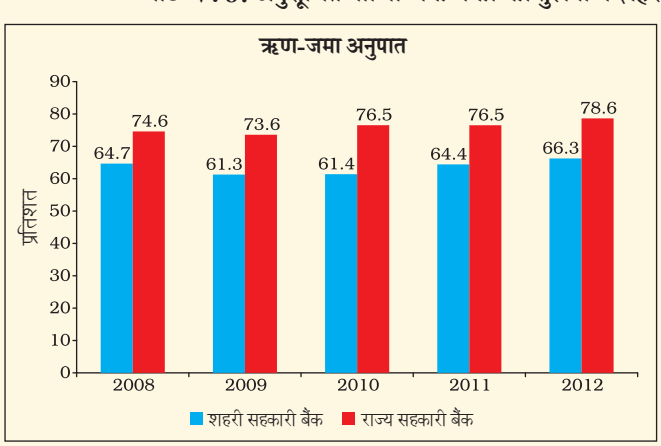

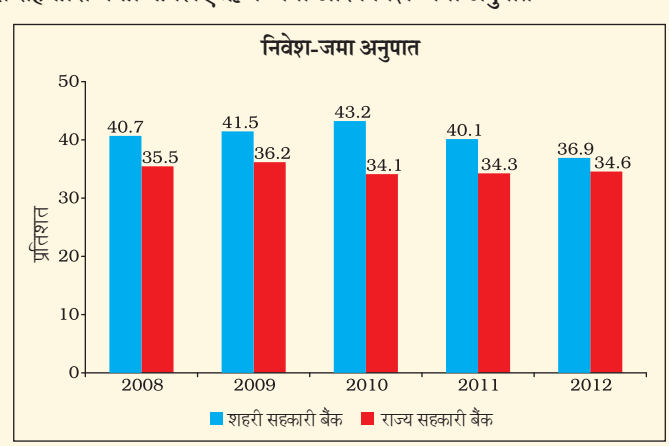

सारणी V.6: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक		प्रतिशत अंतर (सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. कुल आय (i+ii)	**98**	**124**	**125**	**158**	**224**	**281**	**13.4**	**25.9**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याज से आय	90	113	119	148	209	261	14.2	25.2
	(91.3)	(91.7)	(95.0)	(93.9)	(93.4)	(92.9)		
ii. ब्याज से इतर आय	9	10	6	10	15	20	2.4	35.4
	(8.7)	(8.3)	(5.0)	(6.1)	(6.6)	(7.1)		
आ. कुल व्यय	**78**	**100**	**107**	**131**	**185**	**230**	**9.6**	**24.9**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याज पर व्यय	55	74	75	92	131	166	8.8	27.2
	(70.9)	(74.3)	(70.6)	(70.5)	(70.8)	(72.1)		
ii. ब्याज से इतर व्यय	23	26	31	39	54	64	11.4	19.1
	(29.1)	(25.7)	(29.4)	(29.5)	(29.2)	(27.9)		
जिसमें से : स्टाफ पर व्यय	12	13	16	19	28	32	-0.3	15.0
इ. लाभ								
i. परिचालनगत लाभ की राशि	20	24	19	27	39	51	35.7	30.7
ii. प्रावधान, आकस्मिकताएं, कर	8	10	9	13	17	23	2.6	37.0
iii. निवल लाभ की राशि	12	14	10	14	22	28	78.0	26.1

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।
2. निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित करने के कारण अंतर के प्रतिशत में कुछ परिवर्तन आ सकता है।
3. पूर्णांकित करने के कारण घटकों से प्राप्त जोड़ अलग हो सकता है।
4. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।

शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा

5.20 शहरी सहकारी बैंकों आस्ति गुणवत्ता में हाल के वर्षों में निरंतर सुधार हुआ है। सकल अनर्जक आस्तियों के निरपेक्ष और आनुपातिक - दोनों रूपों में कमी आई है। इसी रुझान को दर्शाते हुए शहरी सहकारी बैंकों ने सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में ऋणात्मक वृद्धि के संबंध में रिपोर्ट किया और 2011-12 मे उनकी सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी हुई है (सारणी V.8 के साथ पठित चार्ट V.9)।

सारणी V.7:शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाभप्रदता के चुनिंदा संकेतक

वित्तीय संकेतक	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिफल	1.07	1.08	0.7	0.9	0.9	1.0
इक्विटी पर प्रतिफल	9.6	10.1	5.5	7.3	7.1	8.4
निवल ब्याज मार्जिन	3.1	3.0	3.1	3.6	3.1	3.3

टिप्पणी: 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट V.9 : सकल अनर्जक आस्तियों की वृद्धि और अनुपात

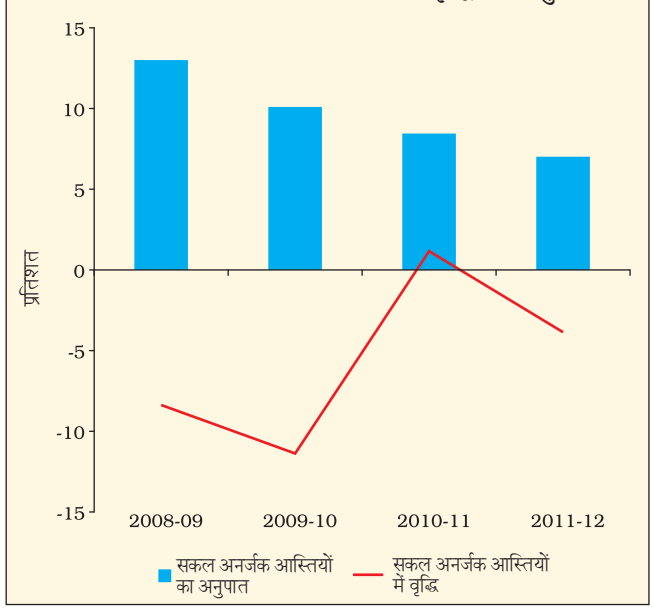

सारणी V.8: शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तिया

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	2011	2012
1	2	3
1. सकल अनर्जक आस्तियां	115	111
2. निवल अनर्जक आस्तियां	27	29
3. सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (प्रतिशत)	8.4	7.0
4. निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (प्रतिशत)	2.1	2.0
5. प्रावधानीकरण (1-2)	88	82
6. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (प्रतिशत) (5/1)	76.6	73.6

शहरी सहकारी बैंकों के लिए बढ़ता हुआ प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

5.21 शहरी सहकारी बैंकों की सिर्फ गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी नहीं आई बल्कि हाल के वर्षों में उनके प्रावधानीकरण में भी नियमित वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, सकल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निरूपित किए जाने वाले उनके प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में भी व्यापक रूप से वृद्धि का रुझान दिखाई दिया (चार्ट V.10)।

2011-12 में अधिकतर शहरी सहकारी बैंकों ने जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के न्यूनतम सांविधिक सीमा से अधिक होने की सूचना दी है किंतु गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी स्थिति ज्यादा कमजोर रही

5.22 अधिकतर (लगभग 91 प्रतिशत) शहरी सहकारी बैंकों ने मार्च 2012 (चार्ट V.11 के साथ पठित सारणी V.9) के अंत में

सारणी V.9: शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के अनुसार वर्गीकरण

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (प्रतिशत में)	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	सभी शहरी सहकारी बैंक
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	8	79	87
3 < सीआरएआर < 6	1	14	15
6 < सीआरएआर < 9	-	50	50
9 < सीआरएआर < 12	8	197	205
12 < सीआरएआर	35	1,226	1,261
जोड़	**52**	**1,566**	**1,618**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के निर्धारित 9 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक सीमा से अधिक होने की सूचना दी है। तथापि, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी स्थिति गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में कहीं अधिक कमजोर रही। इसके अलावा, विनियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात वाले अधिकतर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात ऋणात्मक होना परेशानी की बात रही।

लघु उद्यम और आवास - 2011-12 में शहरी सहकारी बैंक ऋणों के प्रमुख घटक

5.23 शहरोन्मुखी होने के कारण शहरी सहकारी बैंक मुख्यतः लघु उद्यमों और आवास क्षेत्र की ऋण संबंधी जरूरतों का ध्यान रखते

चार्ट V. 10 : शहरी सहकारी बैंकों का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

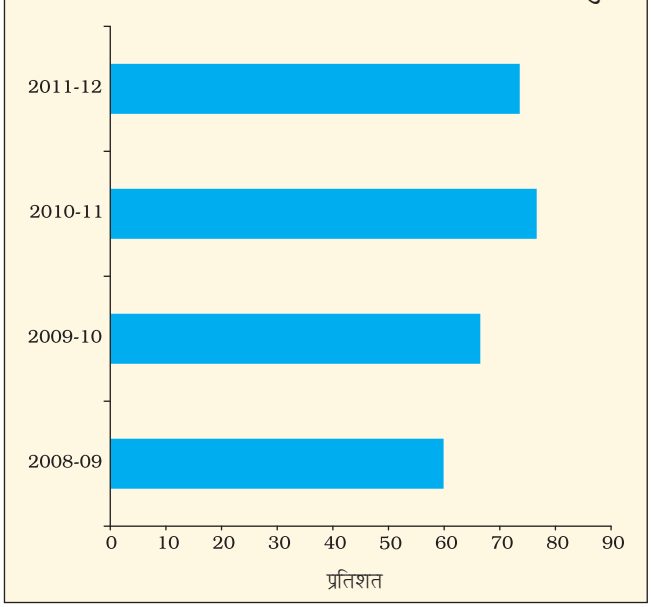

चार्ट V.11: शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के अनुसार वर्गीकरण, 2012

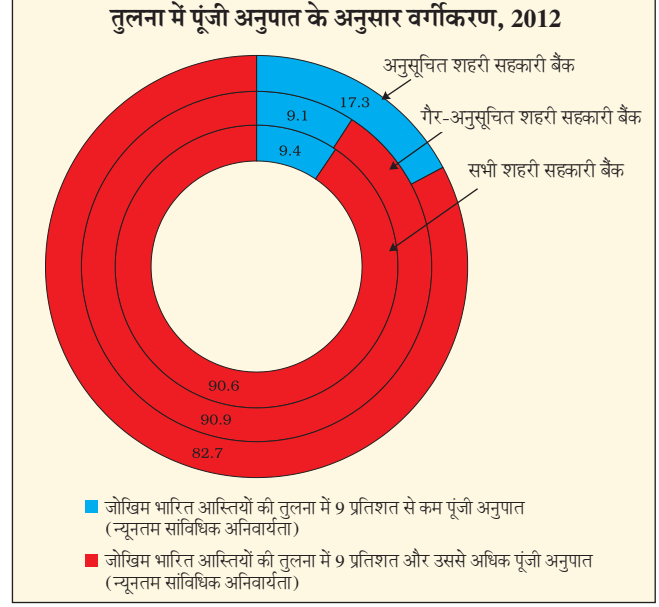

चार्ट V.12: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा चुनिंदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण का प्रतिशत

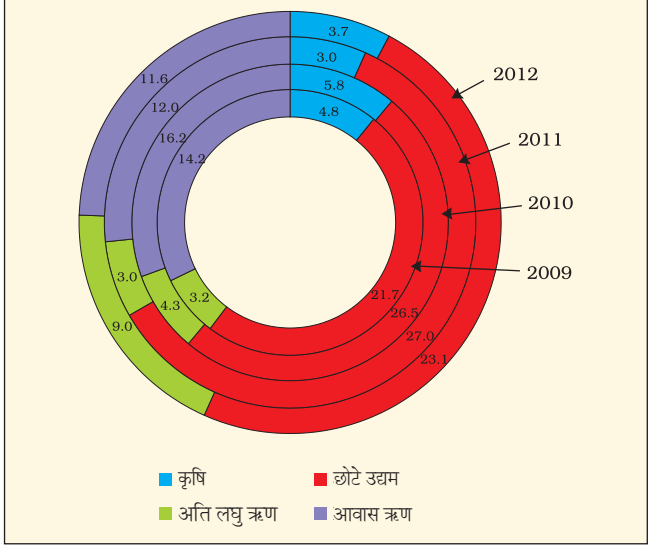

हैं। 2011-12 में शहरी सहकारी बैंकों के कुल ऋण का एक तिहाई से अधिक भाग इन दोनों क्षेत्रों के हिस्से में गया (सारणी V.10 के साथ पठित चार्ट V.12)। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत रहा।

शहरी सहकारी बैंकों के माइक्रो क्रेडिट के प्रावधान में वृद्धि

5.24 शहरी सहकारी बैंकों के लिए अति लघु ऋण, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का एक घटक है, का महत्त्व काफी बढ़ गया। 2011-12 में प्राथमिकता क्षेत्र के कमजोर तबकों को अति लघु ऋण वितरण में काफी तेजी रही जिसे वित्तीय समावेशन में शहरी सहकारी बैंकों की योगदान के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार के ऋण वितरण की शहरी सहकारी बैंकों के दो प्रमुख प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों, आवास और लघु उद्यमों से नजदीकी प्रतिस्पर्द्धा रही। (चार्ट V.14)।

शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार का अधिक किंतु घटता भौगोलिक संकेंद्रण

5.25 ऋण और जमाराशि द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के आया बैंकिंग कारोबार स्थानिक रूप से पश्चिमी क्षेत्र में और उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रित रहा। ये दोनों क्षेत्र भारत के कुल जिलों के मात्र 27 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग कारोबार के 92 प्रतिशत को नियत्रित करते हैं (अनुबंध सारणी V.3 के साथ पठित सारणी V.11)। दूसरी ओर, शेष चार क्षेत्र कुल जिलों के लगभग 73 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं

सारणी V.10: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण की संरचना

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

क्षेत्र	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल ऋण की संरचना		*जिसमें से,* कमजोर वर्ग को दिया गया ऋण	
	राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कृषि ऋण	**58**	**3.7**	**21**	**1.3**
1.1 प्रत्यक्ष कृषि ऋण	19	1.2	8	0.5
1.2 अप्रत्यक्ष कृषि ऋण	39	2.5	13	0.8
2. लघु उद्यम	**366**	**23.1**	**74**	**4.7**
2.1 लघु उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण	306	19.5	58	3.7
2.2 लघु उद्यमों को अप्रत्यक्ष ऋण	60	3.9	16	1.0
3. अति लघु ऋण	**142**	**9.0**	**41**	**2.6**
3.1 स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह को ऋण	10	0.6	3	0.2
3.2 अन्य को दिया गया ऋण	132	8.5	38	2.4
4. अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए राज्य प्रायोजित संगठन	**2**	**0.1**	**1**	**0.03**
5. शिक्षा ऋण	**20**	**1.2**	**7**	**0.4**
6. आवास ऋण	**183**	**11.6**	**53**	**3.4**
सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**770**	**48.7**	**195**	**12.4**

टिप्पणी: 1. प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के कुल ऋणों के संदर्भ में दिया गया है।
2. पूर्णांकित करने के कारण घटकों से प्राप्त जोड़ अलग हो सकता है।.

परंतु शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग कारोबार में उनका हिस्सा 9 प्रतिशत से भी कम है। प्रति-शाखावार बैंकिंग कारोबार भी पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में काफी अधिक रहा (सारणी V.12)।

चार्ट V.13: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग को दिए गए ऋण वितरण का प्रतिशत

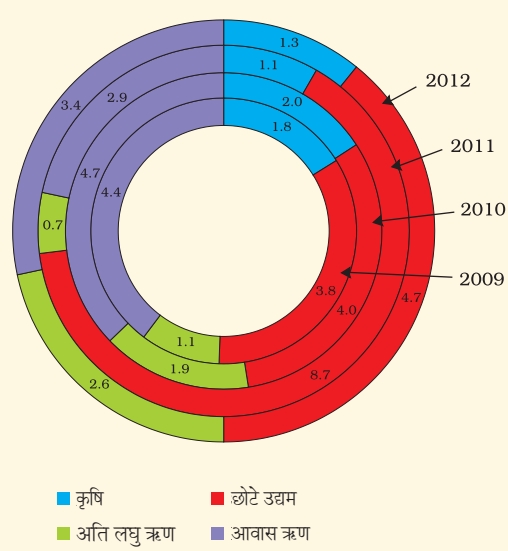

सारणी V.11: सभी क्षेत्रों में शहरी सहकारी बैंकों के जिलों और बैंकिंग व्यवसाय का विन्यास

क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग व्यवसाय में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3
	कम संकेंद्रण वाले क्षेत्र	
उत्तरी क्षेत्र	17.5	3.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	9.9	0.4
पूर्वी क्षेत्र	18.3	1.7
केंद्रीय क्षेत्र	27.0	3.2
उप-जोड़	**72.7**	**8.5**
	अधिक संकेंद्रण वाले क्षेत्र	
पश्चिमी क्षेत्र	10.4	76.2
दक्षिणी क्षेत्र	17.0	15.3
उप जोड़	**27.4**	**91.5**
संपूर्ण भारत	**100.0**	**100.0**

टिप्पणी: बैंकिंग व्यवसाय का तात्पर्य शहरी सहकारी बैंकों के क्रेडिट और जमाराशियों से है।

5.26 ध्यान देने की बात है कि शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार के संकेंद्रण में समय बीतने के साथ कुछ कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। 2009 और 2012 के बीच सभी क्षेत्रों के शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार में अंतर के गुणांक से पता चलता है कि कारोबार के संकेंद्रण में धीमी किंतु सतत् गिरावट आई है (सारणी V.12)।

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं [4]

ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे पर अल्पावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं का दबदबा कायम है

5.27 ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे पर, कई वर्षों से, अल्पावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही दीर्घावधि ऋण ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं का हिस्सा निरंतर कम होता जा रहा है (सारणी V.13 के साथ पठित चार्ट V.14)[5]।

दीर्घावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं की तुलना में अल्पावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं की लाभप्रदता का पुनरुज्जीवन

5.28 अल्पावधि ऋण ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं की लाभप्रदता का 2008-09 से समग्ररूप से पुनरुज्जीवन हुआ। यह

सारणी V.12: शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में क्षेत्रवार प्रति शाखा बैंकिंग कारोबार की मात्रा

क्षेत्र	प्रति शाखा बैंकिंग कारोबार (मिलियन रुपये में)		
	2009	2011	2012
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	290	320	367
पूर्वोत्तर क्षेत्र	151	262	313
पूर्वी क्षेत्र	342	403	445
केंद्रीय क्षेत्र	234	285	290
पश्चिमी क्षेत्र	395	490	557
दक्षिणी क्षेत्र	214	289	332
संपूर्ण भारत	**341**	**426**	**481**
भिन्नता गुणांक	*0.33*	*0.26*	*0.25*

क्रम पहले के वर्षों के विपरीत है जब इन सहकारी संस्थाओं द्वारा लगातार अपने घाटे के बढ़ने की जानकारी दी जाती थी। अल्पावधि ऋण ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज के रुप में कई राज्यों द्वारा लागू की गई एक समान सुधार प्रक्रिया भी इनकी लाभप्रदता में सुधार होने का कारण हो सकती है।[5] दूसरी ओर दीर्घावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं की लाभप्रदता में

चार्ट V.14: अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण सहकारी समितियों के अनुसार ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की संरचना

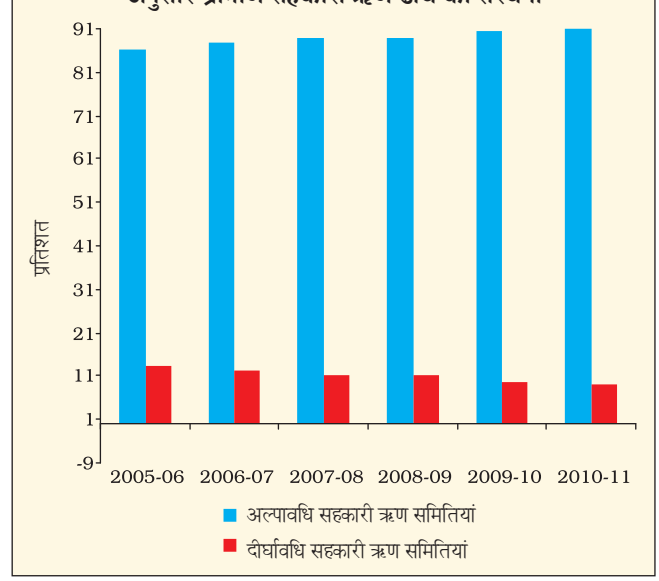

[4] ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के आंकड़ों की उपलब्धता में विलंब होने के कारण यह खंड 2010-11 पर आधारित है।

[5] अल्पावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज का विवरण बाद में खंड 5में दिया गया है।

सारणी V.13: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का प्रोफाइल

(31 मार्च 2011 की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

Item	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	राज्य सहकारी बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
1	2	3	4	5	6
अ. सहकारी संस्थाओं की संख्या	31	370	93,413	20	697
आ. तुलन पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियां (पूंजी + आरक्षित निधियां)	112	242	145	45	49
ii. जमाराशियां	783	1,651	372	10	5
iii. उधार	319	424	540	162	128
iv. ऋण और अग्रिम	640	1,308	878	178	116
v. कुल देयताएं/आस्तियां	1,302	2,541	1,442+	285	252
इ. वित्तीय निष्पादन					
i. लाभ कमाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	30	318	44,554	9	329
ख. लाभ की राशि	5.2	14	18	1	2
ii. घाटा उठाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	1	52	38,065	10	368
ख. घाटे की राशि	0.6	5	20	4	4
iii. समग्र लाभ (+) / हानि (-)	4.6	9	-2	-3	-2
ई. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	57	153	227++	61	48
ii. बकाया कर्ज के प्रतिशत के	8.9	11.6	25.2	34.3	41.7
उ. मांग की तुलना में ऋण वसूली का अनुपात (प्रतिशत)	91.8	78.8	-	40.0	39.4

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक। डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक। पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
-: उपलब्ध नहीं है। +: कार्यशील पूंजी। ++: कुल बकाया राशि
टिप्पणी: मणिपुर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कार्यशील नहीं है।
स्रोत: नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ।

लगातार गिरावट का रुख जारी है और इनके भी पुनरुज्जीवन के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं (चार्ट V.15)।

चार्ट V.15: ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की लाभप्रदता

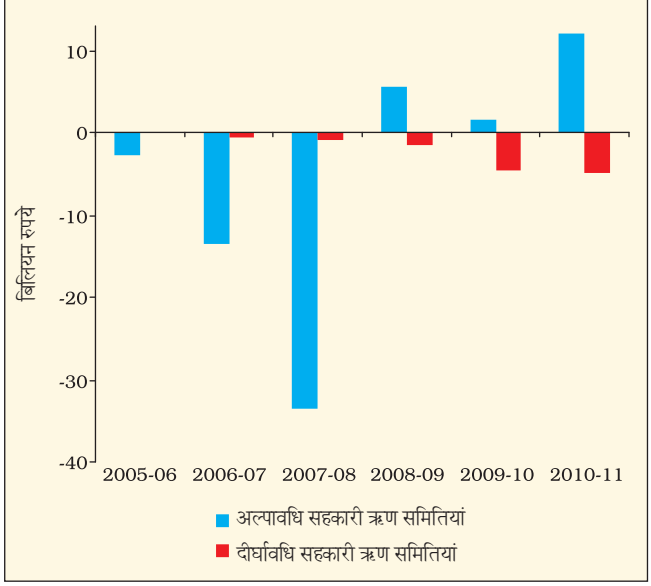

अल्पावधि ऋण देने वाली ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

राज्य सहकारी बैंक

वर्ष 2010-11 में राज्य सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र के आकार की वृद्धि में कमी आई

5.29 2009-10 की तुलना में 2010-11 में राज्य सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र के आकार की वृद्धि में कमी आई है। राज्य सहकारी बैंकों के 2010-11 के तुलन-पत्र के देयता पक्ष में वृद्धि उधार राशियों में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई थी, जबकि आस्ति पक्ष में, वृद्धि के लिए उधार एवं अग्रिम या ऋण उत्तरदायी हैं (सारणी V.14)।

2011-12 में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र के आकार की वृद्धि में कमी आने की संभावना

5.30 हाल की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने के लिए धारा 42(2) के अंतर्गत विवरणियों से 2011-12 के लिए अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त अग्रिम जानकारी का विश्लेषण किया गया जा रहा है। प्रवृत्तियों से यह संकेत मिलता है कि 2011-12 के दौरान अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की जमाराशियों और एसएलआर

सारणी V.14: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां
(मार्च 2011 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत विचलन	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	16	21	4.0	25.8
	(1.3)	(1.6)		
2. आरक्षित निधियां	76	91	-26.3	19.8
	(6.2)	(7.0)		
3. जमाराशियां	812	783	15.5	-3.6
	(66.1)	(60.2)		
4. उधार	234	319	12.0	36.3
	(19.1)	(24.5)		
5. अन्य देयताएं	90	88	79.1	-1.8
	(7.3)	(6.8)		
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	105	84	32.4	-20.8
	(8.6)	(6.4)		
2. निवेश	553	502	18.9	-9.2
	(45.1)	(38.6)		
3. ऋण और अग्रिम	493	640	1.8	29.8
	(40.1)	(49.1)		
4. अन्य आस्तियां	76.7	76.8	47.8	0.2
	(6.2)	(5.9)		
कुल देयताएं/ आस्तियां	**1,228**	**1,302**	**13.6**	**6.0**
	(100.0)	**(100.0)**		

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण विचलन के प्रतिशत में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: नाबार्ड

निवेश - दोनों की वृद्धि का पुनरुज्जीवन होने के बाद भी इस वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की वृद्धि में कमी आई है (सारणी V.15)।

सारणी V.15: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
जमाराशियां	652	594	640
	(24.0)	(-8.9)	(7.8)
ऋण	433	587	694
	(2.3)	(35.4)	(18.3)
एसएलआर निवेश	239	213	209
	(39.2)	(-10.8)	(-1.8)
ऋण + एसएलआर निवेश	673	800	904
	(12.9)	(19.0)	(12.9)

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि को सूचित करते हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण विचलन के प्रतिशत में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत अंतिम फॉर्म ए/बी

आय में उच्चतर वृद्धि के कारण 2010-11 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में बदलाव

5.31 वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों का निवल लाभ लगभग दोगुना हो गया, जो वर्ष 2009-10 में इन संस्थानों के द्वारा लाभ में दर्शायी गयी ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में पूरी तरह बदलाव दर्शाता है (सारणी V.16)। राज्य सहकारी बैंकों के व्यय की तुलना में आय में अधिक वृद्धि होने के कारण लाभप्रदता में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज से आय में उच्चतर वृद्धि के कारण हुई।

5.32 राज्य सहकारी बैंकों के कुल व्यय के अंतर्गत, प्रावधानों और आकस्मिक व्यय में और तीव्र वृद्धि हुई, जो कुछ हद तक 2010-11 के दौरान इन संस्थाओं की अनर्जक आस्तियों में हुई तीव्र वृद्धि के कारण आवश्यक हो गया था।

सामान्यरूप से अनर्जक आस्ति अनुपात को नियंत्रित रखे जाने के बाद भी वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों में अधिक वृद्धि हुई

5.33 वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों की स्थिति खराब हुई। तथापि राज्य सहकारी बैंकों द्वारा

सारणी V.16: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	निम्नलिखित के दौरान		प्रतिशत विचलन	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**82**	**87**	**8.8**	**5.9**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज से आय	78	83	7.6	6.5
	(94.9)	(95.5)		
ii. अन्य आय	4.2	3.9	38.0	-5.4
	(5.1)	(4.5)		
आ. व्यय (i+ii+iii)	**80**	**83**	**10.1**	**3.4**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज व्यय	66	68	15.3	2.7
	(82.5)	(82.0)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	3.96	4.05	-10.2	2.1
	(5.0)	(4.9)		
iii. परिचालन व्यय	10	11	-8.6	8.0
	(12.5)	(13.1)		
जिनमें से, मजदूरी बिल	6	7	-14.4	18.3
	(7.3)	(8.3)		
इ. लाभ				
i. परिचालन लाभ	6.4	8.7	-15.0	35.2
ii. निवल लाभ	2.4	4.6	-21.7	88.8

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय का प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण विचलन के प्रतिशत में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: नाबार्ड.

दिए जाने वाले ऋण में हुई अधिक वृद्धि को देखते हुए वर्ष 2010-11 के दौरान अनर्जक आस्ति अनुपात (जो बकाया ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात होता है) मोटे तौर पर 8.9 प्रतिशत के आस-पास बनाए रखा गया (सारणी V.17)। वर्ष 2010-11 में अनर्जक आस्तियों की उच्च वृद्धि अवमानक आस्तियों के कारण हुई क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों की वृद्धि में मामूली नरमी दिखाई दी। अनर्जक आस्ति अनुपात की तरह, वर्ष 2010-11 में मांग की तुलना में वसूली अनुपात जो प्रत्याशित वसूली के अनुपात के रूप में ऋण की वसूली की संभाव्यता दर्शाता है, 92 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है।

राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ

5.34 हाल के वर्षों में राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में स्पष्ट सुधार के लक्षण दिखाई दिए हैं। 2008 से 2011 के बीच राज्य सहकारी बैंकों के अनर्जक आस्ति अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह अनुपात या तो घटा है या अधिक-से-अधिक पिछले वर्ष के स्तर पर रहा है (चार्ट V.16)। वसूली अनुपात में भी ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई दी जिसमें अनुपात या तो बढ़ा है या अपरिवर्तित रहा है।

पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों के राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार हुआ

5.35 अनर्जक आस्ति और वसूली अनुपात से मिलने वाले संकेतों के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों के राज्य सहकारी

चार्ट V.16: राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के संकेतक

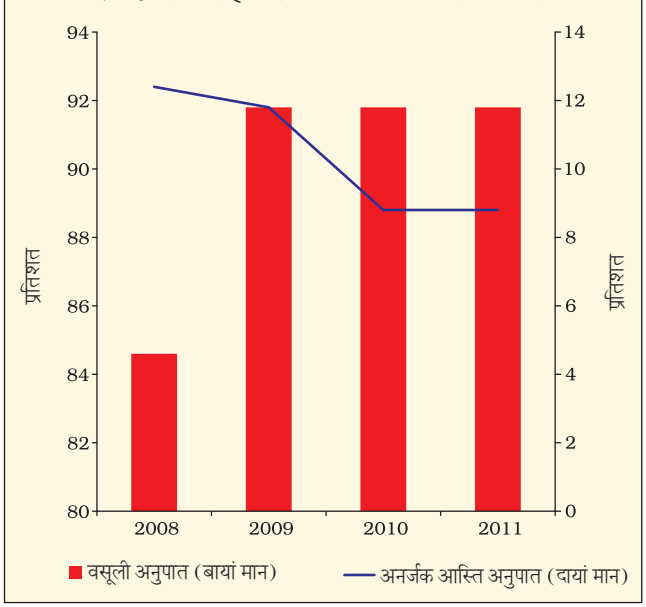

सारणी V.17: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत विचलन	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
अ. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	44	57	-24.5	31.4
i. अवमानक	13	17	-20.6	28.7
	(30.6)	(30.0)		
ii. संदिग्ध	22	25	42.3	12.9
	(51.0)	(43.8)		
iii. हानि	8	15	231.0	86.9
	(18.4)	(26.2)		
आ. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**8.8**	**8.9**	-	-
इ. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	**91.8**	**91.8**	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण विचलन के प्रतिशत में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार देखा जा सकता है (परिशिष्ट सारणी V.4 के साथ पठित चार्ट V.17)। पश्चिमी क्षेत्र में अनर्जक आस्ति अनुपात बढ़ने और वसूली अनुपात घटने की प्रवृत्ति दिखाई दी जो अन्य सभी क्षेत्रों में देखी गई प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत है।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंकों की तरह, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र की वृद्धि में कमी आयी

5.36 2010-11 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की तरह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के (जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों) तुलन-पत्र में भी गिरावट दिखाई दी (सारणी V.18)। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में कमी, देयता पक्ष में जमाराशियों में तथा आस्ति पक्ष में निवेश में आयी कमी का परिणाम है, हालांकि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ऋण वृद्धि में बढ़त दर्ज की गई।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लाभ में गिरावट की प्रवृत्ति

5.37 यद्यपि 2010-11 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने समग्र रूप से लाभ दर्शाया है, तथापि इन संस्थाओं के लाभ की मात्रा में गिरावट आई है (सारणी V.19)। लाभप्रदता में गिरावट का मुख्य कारण परिचालन खर्च में हुई उच्च वृद्धि है जो इन संस्थाओं की आय में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक थी।

चार्ट V.17: राज्य सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति

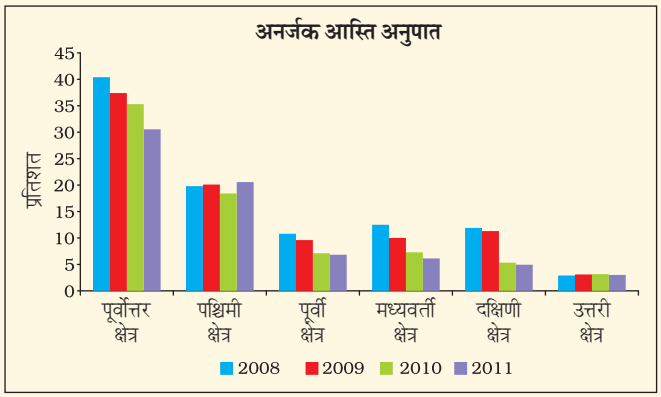

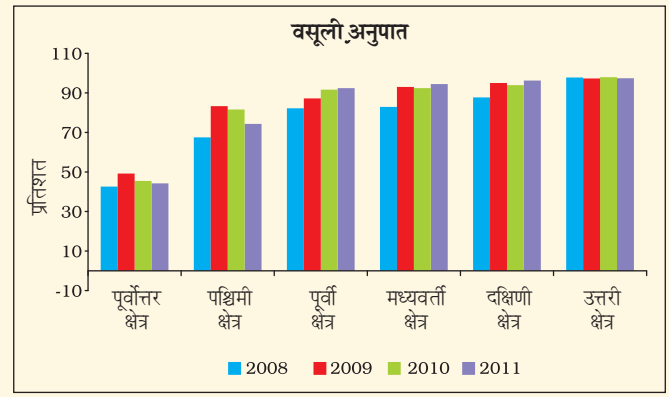

स्रोत : नाबार्ड

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में कुछ और सुधार हुआ

5.38 2010-11 में अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट के साथ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ (सारणी V.20)। इसके अलावा, राज्य सहकारी बैंकों के मामले में देखी गयी प्रवृत्ति के विपरीत, 2009-10 तथा 2010-11 के बीच जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्ति में निरपेक्ष रूप में गिरावट आयी (सारणी V.17 के साथ पठित सारणी V.20)। 2010-11 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वसूली अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई।

सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घटबढ़	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	73	79	11.3	8.5
	(3.2)	(3.1)		
2. आरक्षित निधियां	144	163	-38.0	13.1
	(6.4)	(6.4)		
3. जमाराशियां	1,529	1,651	19.8	8.0
	(67.8)	(65.0)		
4. उधार	287	424	3.6	47.9
	(12.7)	(16.7)		
5. अन्य देयताएं	222	224	109.2	1.2
	(9.8)	(8.8)		
आस्तियां				
1. नकदी एवं बैंक शेष	154	171	19.1	11.4
	(6.8)	(6.7)		
2. निवेश	789	854	21.9	8.2
	(35.0)	(33.6)		
3. ऋण और अग्रिम	1,106	1,308	11.2	18.3
	(49.1)	(51.5)		
4. अन्य आस्तियां	206	208	10.3	1.2
	(9.1)	(8.2)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**2,254**	**2,541**	**15.2**	**12.7**
	(100.0)	**(100.0)**		

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्तियों/देयताओं का प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	निम्नलिखित के दौरान		प्रतिशत घटबढ़	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**177**	**188**	**10.0**	**6.3**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज आय	159	176	9.0	10.7
	(90.0)	(93.7)		
ii. अन्य आय	18	12	19.4	-33.6
	(10.0)	(6.3)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**166**	**179**	**12.1**	**8.0**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. खर्च किया गया ब्याज	103	111	11.8	7.3
	(62.3)	(61.9)		
ii. प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	22.3	21.9	4.1	-1.9
	(13.4)	(12.2)		
iii. परिचालन व्यय	40	46	17.8	15.1
	(24.2)	(25.9)		
जिसमें से, वेतन बिल	26	31	16.7	18.2
	(15.8)	(17.3)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	34	31	-2.7	-7.5
ii. निवल लाभ	11	9	-13.7	-18.6

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय का प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.20: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घटबढ़	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
अ. कुल अनर्जक आस्ति (i+ ii + iii)	**164**	**153**	**-8.7**	**-6.9**
i) अवमानक	73	60	-9.4	-17.1
	(44.4)	(39.6)		
ii) संदिग्ध	64.8	65.0	-10.3	0.3
	(39.6)	(42.6)		
iii) हानि	26	27	-1.8	3.5
	(16.0)	(17.8)		
ब. ऋण-अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**14.8**	**11.6**	-	-
स. मांग-वसूली अनुपात (%)	**75.7**	**78.8**	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट V.18 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय स्थिति के संकेतक

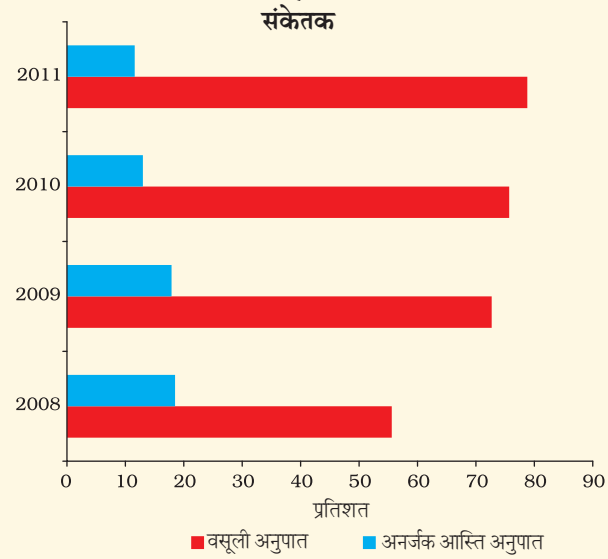

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकलित।

राज्य सहकारी बैंकों की तरह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में स्पष्ट सुधार

5.39 हाल के वर्षों में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में स्पष्ट सुधार हुआ जिसका आंशिक कारण इन संस्थाओं के लिए लागू किए गये सुधार पैकेज का परिणाम है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वसूली अनुपात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई जबकि अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट दर्ज की गई (चार्ट V.18)।

सभी क्षेत्रों में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत

5.40 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में समग्र स्थर पर सुधार हुआ लेकिन इस सुधार का विस्तार सभी क्षेत्रों में नहीं हुआ (परिशिष्ट सारणी V.5 के साथ पठित चार्ट V.19)। एक ओर, दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों में जिला मध्यवर्त्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ रही, जैसाकि दर्शाए गए कम अनर्जक आस्ति अनुपात व उच्च वसूली अनुपात से दिखाई देता है, दूसरी ओर, मध्य, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत कम सुदृढ़ दिखायी दी। तथापि, हाल के वर्षों में इन दोनों संकेतकों के संदर्भ में क्षेत्रीय अंतराल काफी कम हुआ है जो देश भर में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता में हुई वृद्धि का संकेत है।

चार्ट V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति

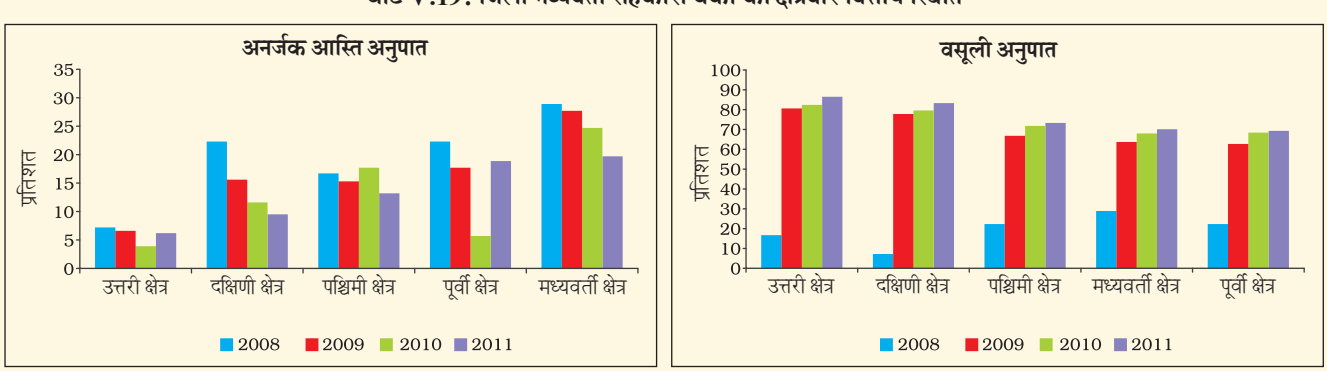

टिप्पणी: पूर्वोत्तर क्षेत्रों में द्विस्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना, जिसमें राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं, होने के कारण वहां जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मौजूद नहीं हैं। अतः इन्हें चार्ट में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड डेटा से परिकलित।

चार्ट V.20: राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति की तुलना

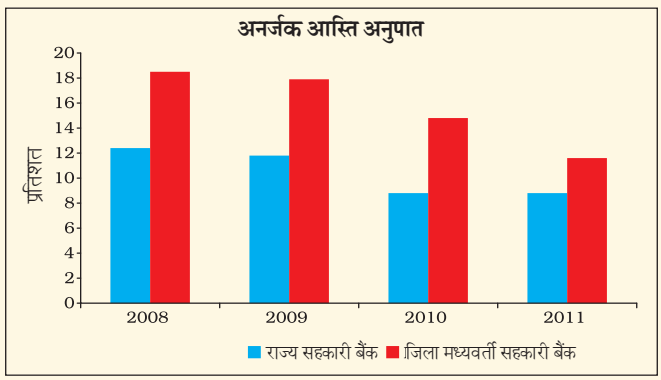

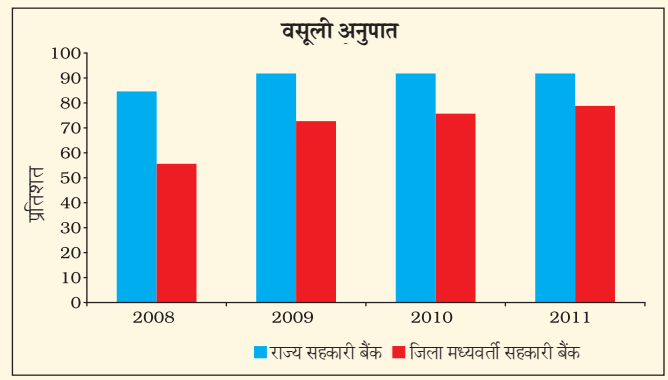

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकलित।

सुधार के बावजूद, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कमजोर रही

5.41 अनर्जक आस्ति अनुपात में कमी तथा वसूली अनुपात में वृद्धि के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सामान्यतः राज्य सहकारी बैंकों की अपेक्षा काफी कमजोर रही (चार्ट V.20)।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

2010-11 में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के ऋणों में धीमी वृद्धि

5.42 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की ऋण वृद्धि 2009-10 की तुलना में 2010-11 में थोड़ी धीमी हुई है (सारणी V.21 के साथ पठित चार्ट V.21)।

चार्ट V.21: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बकाया ऋण में वृद्धि

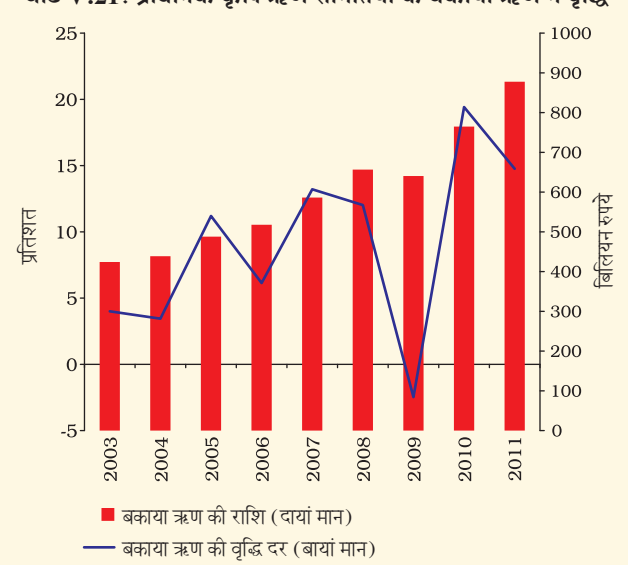

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सदस्य - उधारकर्ता अनुपात लगातार कम रहा

5.43 सदस्य-उधारकर्ता अनुपात प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से ऋण लेने का एक उपयोगी संकेतक है। यह अनुपात 2003 से सामान्यतः हमेशा 50 प्रतिशत से कम रहा है जो यह बताता है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लगभग आधे सदस्य ही प्रत्येक वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त कर पाते हैं।[6] इतना ही नहीं, पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच यह अनुपात

सारणी V.21: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां -चयनित तुलन-पत्र संकेतक

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घटबढ़
	2010	2011	2010-11
1	2	3	4
क. देयताएं			
1. कुल संसाधन (2+3+4)	995	1,057	6.2
2. स्वाधिकृत निधियां (अ+आ)	125	145	15.9
अ. प्रदत्त पूंजी	72	76	5.6
जिसमें से, सरकार का अंशदान	7	6	-6.1
आ. कुल आरक्षित निधियां	53	69	29.5
3. जमाराशियां	353	372	5.5
4. उधार	518	540	4.3
5. कार्यशील पूंजी	1,352	1,442	6.7
ख. आस्तियां			
2. कुल बकाया ऋण (अ+आ)	765	878	14.8
अ) अल्पावधि	550	636	15.8
आ) मध्यावधि	215	241	12.2

टिप्पणी: पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर आ सकता है।
स्रोत: एनएएफएससीओबी।

[6] अनुपात सिर्फ 2007-08 में उधारकर्ताओं की संख्या में 65 प्रतिशत की तेज वृद्धि के कारण बढ़कर 60 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गया। तथापि पिछले तथा बाद के वर्षों में जारी प्रवृत्ति को देखकर यह बहिर्वासी प्रतीत होता है।

चार्ट V.22: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सदस्य-उधारकर्ता अनुपात

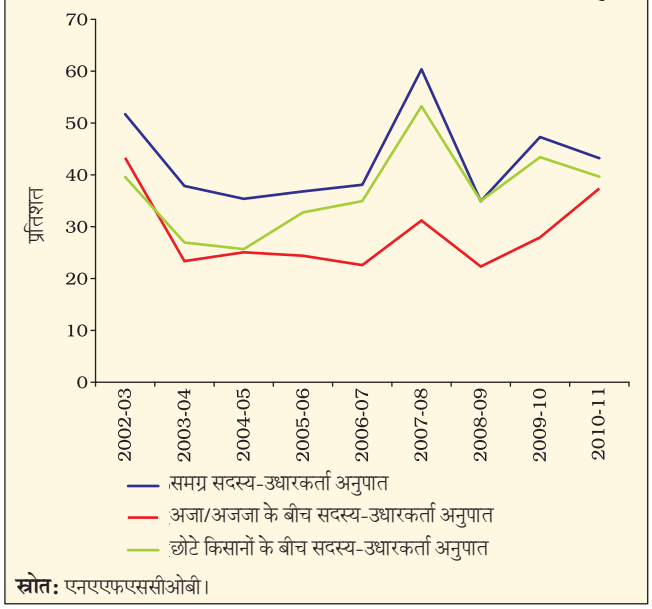

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

सामान्यतः 30 प्रतिशत के नीचे रहा। छोटे किसानों के बीच भी यह अनुपात सदस्य-समग्र उधारकर्ता अनुपात की अपेक्षा कम था (चार्ट V.22)।

घाटे में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या में धीमी गिरावट की प्रवृत्ति

5.44 हाल के वर्षों में, विशेषतः 2008 से, घाटे में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रतिशत में धीमी गिरावट देखी गई। गिरावट के बावजूद, घाटे में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रतिशत के लगभग बराबर था (चार्ट V.23)[7]।

5.45 घाटे में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सबसे अधिक था (परिशिष्ट सारणी V.6 के साथ पठित चार्ट V.23)।

दीर्घावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

2010-11 में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तुलन-पत्र का विस्तार

5.46 2010-11 में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के तुलन-पत्र में उधार ली गई राशि में उच्च वृद्धि सामने आयी जो इन संस्थाओं की कुल देयताओं का लगभग 60 प्रतिशत थी। आस्तियों के संबंध में, वृद्धि का मुख्य प्रेरक ऋण था जो इन संस्थाओं की कुल आस्तियों के 60 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था (सारणी V.22)।

5.47 अल्पावधि तथा दीर्घावधि सहकारी ढांचे के शीर्ष-स्तर की संस्थाओं के तुलन-पत्रों की तुलना करने पर, हाल के वर्षों में राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के घटते आस्ति तथा ऋण आकार एवं कमजोर होती पूंजीगत स्थिति का स्पष्ट पता चला है (बॉक्स V.2)।

चार्ट V.23: लाभ तथा हानि में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत

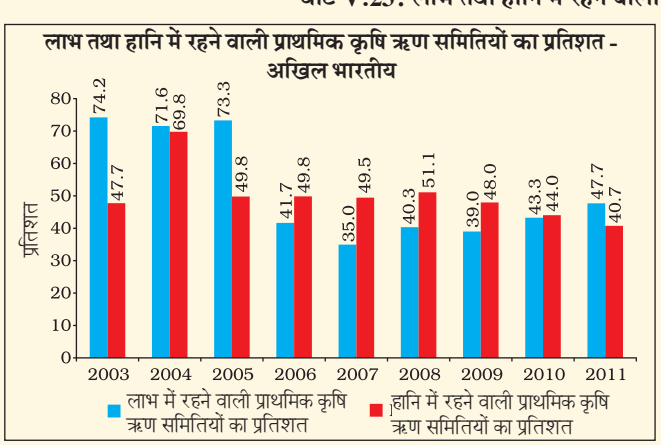

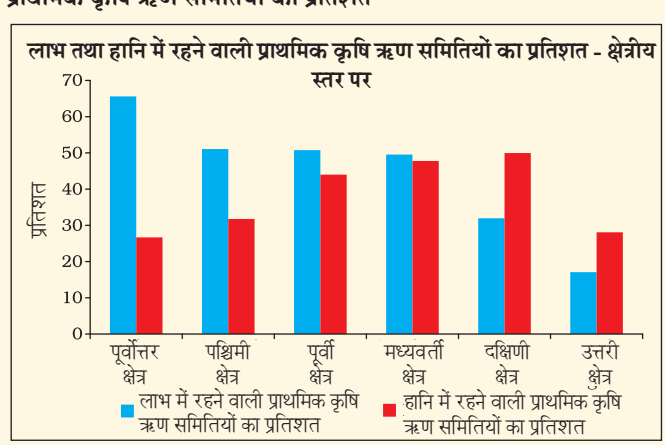

[7] शेष प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संबंध में या तो वे ब्रोकईवन की स्थिति थी, वे न लाभ और न हानि दर्ज कर सकीं, या फिर उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

सारणी V.22: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घटबढ़	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	8.2 (3.2)	8.4 (3.0)	1.0	2.5
2. आरक्षित निधियां	34 (13.4)	37 (13.0)	7.3	7.8
3. जमाराशियां	8 (3.0)	10 (3.3)	6.7	25.2
4. उधार	156 (61.0)	162 (57.0)	-1.7	4.2
5. अन्य देयताएं	50 (19.5)	68 (23.7)	3.2	35.7
आस्तियाँ				
1. नकदी और बैंक शेष	2.0 (0.8)	2.4 (0.8)	4.3	19.6
2. निवेश	31 (12.3)	29 (10.0)	6.8	-9.2
3. ऋण और अग्रिम	170 (66.5)	178 (62.6)	3.5	4.8
4. अन्य आस्तियाँ	52 (20.4)	76 (26.6)	-10.5	45.0
कुल देयताएं/आस्तियां	**256 (100.0)**	**285 (100.0)**	**0.7**	**11.4**

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आस्तिओं/देयताओं के प्रतिशत हैं।
2. मणिपुर में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सक्रिय नहीं है।
3. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को पूर्व की भांति 2010-11 में भी हानि हुई

5.48 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने वर्ष 2009-10 की तरह ही वर्ष 2010-11 में भी हानि की रिपोर्ट भेजी है। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की यह हानि कुल आय में ऋणात्मक वृद्धि के साथ-साथ ब्याज में अधिक तेजी के साथ वृद्धि तथा परिचालन व्यय में तेज वृद्धि के कारण उनके कुल खर्च में वृद्धि होने के कारण हुई (सारणी V.23)।

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की कमजोर आस्ति गुणवत्ता

5.49 लगभग 34 प्रतिशत अनर्जक आस्ति अनुपात के साथ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता कमजोर रही है (सारणी V.24)। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों के साथ तुलना यह दर्शाती है कि राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता बहुत निराशाजनक है। इसके अतिरिक्त, राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति के विपरीत राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्ति अनुपात में हाल के वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई है (चार्ट V.24)।

पश्चिमी क्षेत्र में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता सबसे कमजोर थी

5.50 पश्चिमी क्षेत्र में देखा गया कि राज्य सहकारी बैंकों की तरह ही राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति अधिक कमजोर थी। मार्च 2011 के अंत में पश्चिमी क्षेत्र में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्तियाँ 74 प्रतिशत के उच्च अनुपात तक रहीं। इससे यह अर्थ निकलता है कि इन संस्थाओं की ऋण आस्ति का केवल एक चौथाई हिस्सा ही मानक आस्ति थे (परिशिष्ट सारणी V.7 के साथ पठित चार्ट V. 25)।

प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2010-11 में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के तुलन- पत्र में आंशिक वृद्धि हुई

5.51 2010-11 में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के तुलन-पत्र में लगभग न के बराबर वृद्धि हुई। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की निधि के उपयोग के बड़े घटक, नामतः ऋण और उनकी निधियों का स्रोत, नामतः उधार में 2010-11 में 1 प्रतिशत से भी कम के लगभग नगण्य वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के समान ही है (सारणी V. 25)।

2010-11 में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तरह ही प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने भी सतत् हानि दर्ज की

5.52 2010-11 में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तरह ही प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों में समग्र स्तर पर हानि दर्ज हुई (सारणी V.26)। वर्ष के दौरान इन संस्थाओं में से अधिक संस्थाओं में हानि हुई है (परिशिष्ट सारणी V.8 के साथ पठित चार्ट V. 26)। इसके अलावा, एक परेशानी यह है कि पिछले कुछ समय में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की लाभप्रदता में कोई प्रत्यक्ष सुधार नहीं हुआ।

वित्तीय स्थिति की दृष्टि से राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तुलना में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बहुत कमजोर थे

5.53 हालांकि दीर्घकालिक सहकारी संरचना मोटे तौर पर कमजोर रही, इस संरचना में हम जैसे-जैसे उच्च टियर से निम्न

बॉक्स V.2: कमजोर होता दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचा: शीर्ष-स्तर की संस्थाओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण

दीर्घावधि ऋण सहकारी संस्थाओं की उत्पत्ति और उनका औचित्य

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में देश में ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं के समाधान के लिए बनायी गई सहकारी संस्थाएं पश्चिमी यूरोपीय देशों में बहुत ही सफल रही कुछ सहकारी समितियों की तर्ज पर बनायी गई प्रथम औपचारिक संस्थाएं थीं। तथापि, अन्य देशों, जिन्होंने ऋण सहकारी संस्थाओं को अपनाया, के विपरीत भारत में दो विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं, जैसे-अल्पावधि तथा दीर्घावधि का निर्माण विशेष विकास उद्देश्यों के साथ किया गया। अल्पावधि सहकारी संस्थाओं का निर्माण, मौसमी कृषिजन्य क्रियाकलापों तथा फसलों के विपणन हेतु किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया, जबकि भूमि बंधक बैंकों के रूप में दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं का निर्माण भूमि विकास के लिए किसानों की दीर्घावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। समय के साथ, इन दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं ने अपने उधार कार्य परिचालनों को विशाखीकृत किया तथा इनके अलग-अलग नाम दिए गये - पहला, भूमि विकास बैंक तथा दूसरा, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (भारत सरकार 2004)।

दीर्घावधि सहकारी ऋण के संवितरण में कमी

हाल के वर्षों में, दीर्घावधि सहकारी ऋणों के संवितरण में स्पष्ट गिरावट आई है (चार्ट नीचे है)। कुल सहकारी ऋण (संवितरित) में दीर्घावधि ऋण की हिस्सेदारी 2000-01 में 32 प्रतिशत रही, जो 2009-10 में लगभग इसकी आधी होकर 17 प्रतिशत रह गयी। यहां तक कि निरपेक्ष संदर्भ में भी, 2000 के दशक के कुछ वर्षों में सहकारी समितियों द्वारा वितरित दीर्घावधि ऋण की राशि में गिरावट आयी थी।

राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों का घटता पूंजी आधार तथा आस्ति आकार

दीर्घावधि तथा अल्पावधि सहकारी संस्थाओं हेतु गठित शीर्ष स्तर की संस्थाओं, नामतः राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन दीर्घावधि तथा अल्पावधि संरचना की वृद्धि के बीच बढ़ते हुए अंतर को दर्शाता है (ऊपर दी गई सारणी देखें)। यह विश्लेषण बताता है कि -

चार्ट: अल्पावधि तथा दीर्घावधि सहकारी ऋणों की राशि

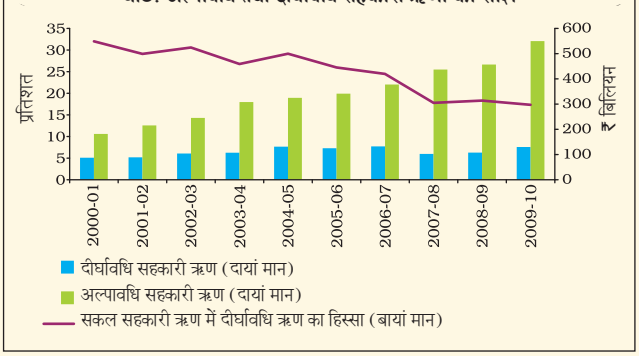

सारणी : एससीएआरडीबी तथा राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति, ऋण तथा पूंजी आकार की तुलना

(₹ में)

वर्ष	राज्य सहकारी बैंकों की आस्तियों के प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में एससीएआरडीबी की आस्तियों की राशि	राज्य सहकारी बैंकों के ऋण के प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में एससीएआरडीबी के ऋण की राशि	राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी की प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में एससीएआरडीबी की पूंजी की राशि
2008	26	37	80
2009	23	34	52
2010	21	34	51
2011	22	28	40

स्रोत: नाबार्ड के आंकड़ों के आधार पर परिकलित।

(अ) 2008 में राज्य सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों के प्रत्येक 100 रुपये के लिए, राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों का आस्ति मूल्य मात्र 26 रुपये था। 2011 तक राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंकों का सापेक्ष आस्ति आकार गिरकर 22 रुपये रह गया।

(आ) संकुचन तब और आश्चर्यजनक था जब राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो के आकार की तुलना राज्य सहकारी बैंकों के साथ की गई। 2008 में राज्य सहकारी बैंक द्वारा सूचित ऋण के प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंक द्वारा सूचित ऋण का मूल्य 37 रुपये था। 2011 तक, राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के लिए यह सापेक्ष राशि घटकर 28 रुपये रह गयी।

(इ) राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंकों का सापेक्ष रूप से कमजोर होना इन संस्थाओं के पूंजी आधार में होनेवाले परिवर्तनों से विशेष रूप से स्पष्ट है। राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी के प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंक की पूंजी की राशि 2008 में 80 रुपये थी। 2011 तक, राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी की सापेक्ष राशि में तेजी से कमी आई तथा वह 2008 में अपने स्तर के आधे तक पहुंच गई।

वर्ष 2004 की वैद्यनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, अल्पावधि सहकारी संस्थाओं के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज का कार्यान्वयन 2006 से जारी है तथा 2012 तक 25 राज्यों ने अपनी अल्पावधि सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के लिए कदम उठाए हैं (इस अध्याय के खण्ड 5 का संदर्भ लें)। तथापि, दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में, ऐसे पैकेज का कार्यान्वयन अभी तक प्रतीक्षित है। स्पष्ट तौर पर, दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं की धारणीयता दबाव में है और इन संस्थाओं को उचित सुधार द्वारा तत्काल पुनरुज्जीवित किए जाने की जरूरत है।

संदर्भ:

भारत सरकार (2004), ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के पुनरुज्जीवन (दीर्घावधि) पर गठित टास्क फोर्स (अध्यक्षः प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन), नई दिल्ली।

टियर की ओर बढ़ते हैं; वित्तीय स्थिति काफी तेजी के साथ कमजोर हुई। दूसरे शब्दों में, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय हालात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तुलना में अधिक कमजोर थी (सारणी V.24 के साथ पठित सारणी V. 27; चार्ट V.27)

4. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की लाइसेंसीकरण में प्रगति

5.54 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस प्राधिकारी (सहकारी सोसाइटियों के लिए यथा लागू) के रूप में

सारणी V.23: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	निम्नलिखित के दौरान		प्रतिशत घटबढ़	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**21**	**19**	**-31.6**	**-6.2**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज आय	17.75	17.81	-36.0	0.4
	(86.3)	(92.4)		
ii. अन्य आय	3	2	19.9	-47.9
	(13.7)	(7.6)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**21**	**22**	**-28.2**	**3.5**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज पर हुआ खर्च	13	14	-0.3	2.8
	(62.4)	(62.0)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	5	4	-65.1	-17.8
	(22.8)	(18.1)		
iii. परिचालन व्यय	3	4	31.6	39.1
	(14.8)	(19.9)		
जिसमें से वेतन व्यय	2	3	20.3	37.5
	(11.0)	(14.6)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	4.2	1.4	-70.9	-67.0
ii. निवल लाभ/हानि	-0.7	-2.7	-	-

नोट: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आस्तिओं/देयताओं के प्रतिशत हैं।
2. मणिपुर में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सक्रिय नहीं है।
3. प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि निरपेक्ष अंकों को रुपये बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

रिज़र्व बैंक ने एक रूपरेखा तैयार की थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं सहकारी वातावरण में संचालित रहें। नाबार्ड के साथ विचार-विमर्श करके रिजर्व बैंक ने

सारणी V.24 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत परिवर्तन	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियाँ (i+ii+iii)	**57**	**61**	**14.2**	**8.3**
i. अवमानक	28	34	-3.7	21.4
	(50.2)	(56.3)		
ii. संदिग्ध	27	26	38.4	-4.5
	(48.3)	(42.6)		
iii. हानि	0.9	0.7	145.7	-18.5
	(1.6)	(1.2)		
ख. ऋण-अनर्जकआस्ति अनुपात (%)	**33.2**	**34.3**	-	-
ग. मांग-वसूली अनुपात (%)	**40.5**	**40.0**	-	-

नोट: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तिओं के प्रतिशत हैं।
2. संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: नाबार्ड

चार्ट V.24: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्ति की अन्य सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थाओं के साथ तुलना

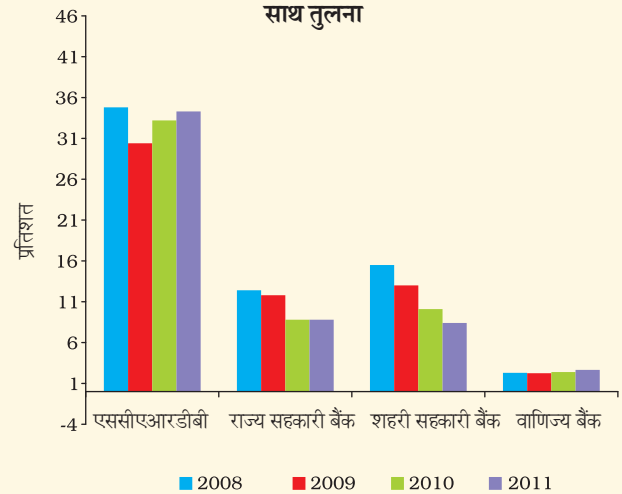

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट के विभिन्न अंकों से संकलित।

2009 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए कि उन्हीं ग्रामीण सहकारी बैंकों को लाइसेंस दिया जाए जिनका नाबार्ड की नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आरक्षित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 4 प्रतिशत और इससे अधिक है और जिन्होंने पिछले एक वर्ष में आरक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात आवश्यकताओं का पालन किया। रिजर्व बैंक ने उसके बाद उक्त शर्तों का पालन करने वाले सहकारी बैंकों को ही लाइसेंस प्रदान किया

चार्ट V.25 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति की क्षेत्रीय तुलना

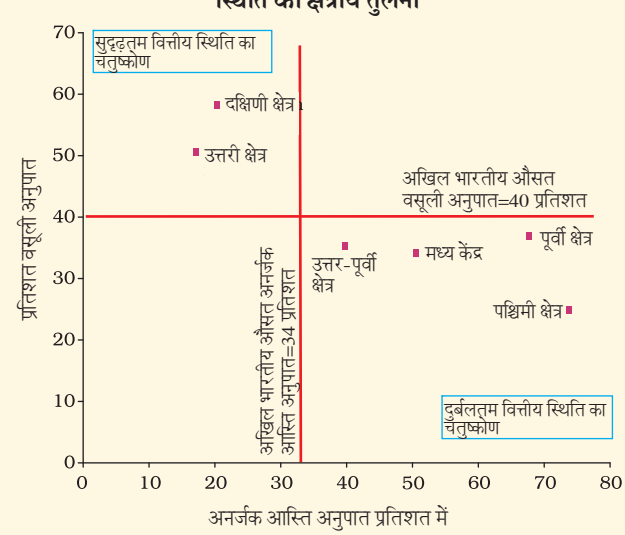

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकलित

सारणी V.25: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियाँ

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत परिवर्तन	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	15.3	14.5	0.8	-4.8
	(6.1)	(5.8)		
2. आरक्षित निधियां	34.74	34.75	-0.5	0.03
	(13.9)	(13.8)		
3. जमाराशियां	4.61	4.58	15.2	-0.5
	(1.8)	(1.8)		
4. उधार राशियां	128.3	128.4	3.8	0.1
	(51.3)	(50.9)		
5. अन्य देयताएं	67	70	-4.7	4.1
	(26.9)	(27.8)		
आस्तियाँ				
1. नकदी और बैंक शेष	2.68	2.73	13.6	2.2
	(1.1)	(1.1)		
2. निवेश	11.7	11.9	4.0	2.3
	(4.7)	(4.7)		
3. ऋण और अग्रिम	114.8	116.1	1.9	1.1
	(45.9)	(46.0)		
4. अन्य आस्तियाँ	121.2	121.7	-0.8	0.5
	(48.4)	(48.2)		
कुल देयताएं/आस्तियाँ	**250**	**252**	**0.8**	**0.8**
	(100.0)	**(100.0)**		

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल आस्तिओं/देयताओं के प्रतिशत हैं।
2. संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.26: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	निम्नलिखित के		प्रतिशत घटबढ़	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**18**	**21**	**-9.4**	**12.4**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज आय	13	15	-9.8	12.3
	(70.5)	(70.5)		
ii. अन्य आय	5.4	6.1	-8.7	12.7
	(29.5)	(29.5)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**22.4**	**22.6**	**0.8**	**0.8**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज पर हुआ खर्च	11.4	11.6	-6.5	1.8
	(50.8)	(51.3)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	6.0	5.8	9.3	-3.3
	(26.6)	(25.5)		
iii. परिचालन व्यय	5.0	5.2	10.1	3.5
	(22.5)	(23.1)		
उक्त में से वेतन व्यय	2.8	2.9	49.2	0.6
	(12.7)	(12.7)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	1.9	3.8	-58.5	100.5
ii. निवल लाभ	-4.1	-2.0	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।
2. संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

है और नाबार्ड के साथ विचार-विमर्श करके लाइसेंस रहित बैंकों की आवधिक समीक्षा भी कर रहा है।

5.55 31 मार्च 2012 तक कुल 43 बैंक, अर्थात 1 राज्य सहकारी बैंक और 42 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लाइसेंस-रहित हैं। लाइसेंस-रहित सहकारी बैंकों के अनुपालन के बारे में एक बार फिर से नाबार्ड के समन्वय से समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और लाइसेंस रहित बैंकों के जमाकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों के लिए यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत लाइसेंस-रहित बैंकों को नई जमा राशियां स्वीकार करने से मना किया जा सकता है।

5.56 इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि एक निगरानी योग्य कार्य योजना के माध्यम से लाइसेंस-रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की प्रगति की सूक्ष्म निगरानी करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह कार्ययोजना संबंधित बैंकों द्वारा तैयार की जाएगी और टास्क फोर्स द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की जाएगी। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक यथासंभव कम-से-कम समय में लाइसेंस जारी

चार्ट V.26 : पीसीएआरडीबी के लाभप्रदता संकेतक

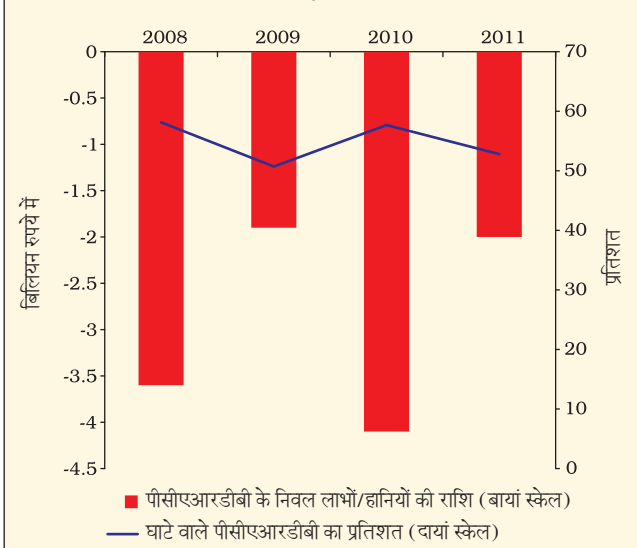

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई गणना।

सारणी V.27: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियाँ (i+ii+iii)	**48.9**	**48.3**	**3.1**	**-1.1**
i. अवमानक	27.7	28.2	0.2	1.7
	(56.7)	(58.4)		
ii. संदिग्ध	20.6	19.5	6.5	-5.0
	(42.1)	(40.4)		
iii. हानि	0.57	0.61	33.7	5.8
	(1.2)	(1.3)		
ख. ऋण-अनर्जक आस्ति अनुपात	**42.6**	**41.7**	-	-
ग. मांग-वसूली अनुपात (%)	**37.2**	**39.4**	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तिओं के प्रतिशत हैं।
2. प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि राशि को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

किये जाने के लिए पात्रता प्राप्त कर लें। टास्क फोर्स उन क्षेत्रों में ऋण के लिए अन्य वैकल्पिक पारंपरिक चैनल की भी जांच करेगा जहाँ ये बैंक कार्यरत थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि लाइसेंस-रहित बैंक लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे तो सामान्य रूप से बैंकिंग सेवाएं तथा अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए और विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

5.57 इसके अलावा, 2012-13 के वार्षिक नीति वक्तव्य में सुझाये गए अनुसार अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी संरचना की समीक्षा करने और मौजूदा तीन टियर संरचना के बजाय दो टियर संरचना की स्थापना की व्यवहार्यता सहित अन्य विकल्पों की खोज करने के लिए जुलाई 2012 में एक कार्य समूह (इस कार्य समूह में बाहर के विशेषज्ञों को शामिल करने के पश्चात ''विशेषज्ञ समिति'' (अध्यक्ष: डॉ. प्रकाश बख्शी) के रूप में पुनः नामकरण किया गया) का गठन किया गया। यह समिति आर्थिक दृष्टि से मजबूत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के साथ आस-पास के जिलों में स्थित कमजोर/अलाभकारी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के विलय की व्यवहार्यता की जांच भी करेगी। इसके साथ जिन स्थानों पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सक्रिय नहीं हैं, यह समिति ग्रामीण ऋण वितरण के लिए वैकल्पिक चैनलों की तलाश करेगी जैसे वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ऋण देना। यह राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा पूँजी-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात में वृद्धि करके 9 प्रतिशत किए जाने की भी जांच करेगा और इन संस्थाओं की पूँजी को बढ़ाने के तरीकों का भी सुझाव देगा।

5. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन में हुई प्रगति

अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन में पर्याप्त प्रगति हुई

5.58 ग्रामीण सहकारिता के क्षेत्र में एक प्रमुख गतिविधि यह रही कि एक व्यावहारिक कार्य योजना द्वारा सहकारी ऋण संस्थाओं (अल्पावधि) के पुनर्जीवन के लिए 2004 में गठित कार्य दल (अध्यक्ष: प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन) के सुझावों का अनुसरण करके उनका पुनरुज्जीवन किया गया है। इस कार्य योजना को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों से मिलकर अंतिम रूप प्रदान किया गया था। समग्रतः इस पैकेज का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना था एवं इन संस्थाओं में विधिक तथा संस्थागत सुधारों को लागू किया जाना है। इन सुधारों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा बॉक्स V. 3 में की गई है।

चार्ट V.27: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तुलना में प्रारम्भिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति

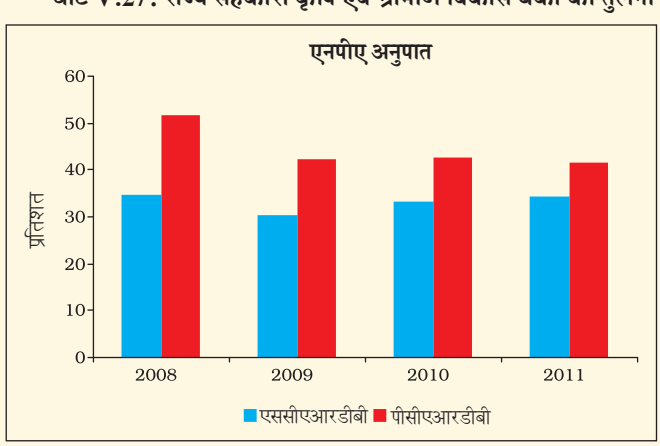

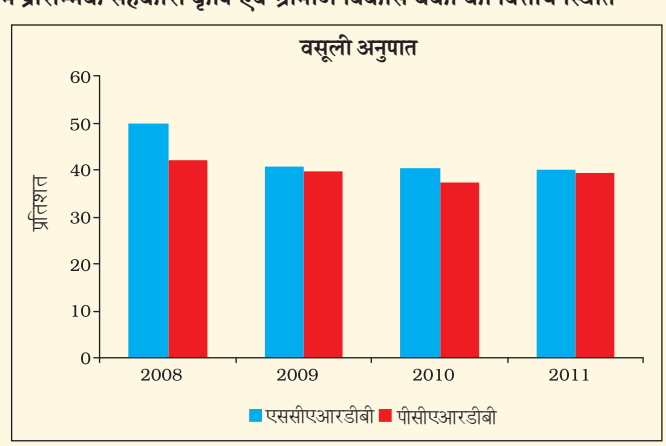

बॉक्स V.3 अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के लिए सुधार

इस कार्य योजना के मुख्य घटक में ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र को पुनर्पूंजीकरण प्रदान करना शामिल है ताकि वह अपने आपको स्वीकार्य आर्थिक स्थिति में ला सके। इसके पश्चात इसका उद्देश्य इन संस्थाओं में कुछ निश्चित विधिक तथा सांस्थानिक सुधार लागू कराना है जिससे इन संस्थाओं में लोकतांत्रिक, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली कार्य-संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

पुनर्पूंजीकरण सहायता

मार्च 2004 के अंत तक के संचयित घाटे को पाटने तथा मार्च 2004 के अंत तक उन्हें जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम 7 प्रतिशत का पूंजी अनुपात प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए 17 राज्यों में स्थित 54,728 अल्पावधि सहकारी संस्थाओं (54,715 प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटीज तथा 13 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) को कुल 98.5 बिलियन रुपये (इसमें भारत सरकार का 90 बिलियन रुपए तथा राज्य सरकार का 8.5 बिलियन रुपये हिस्सा शामिल है) प्रदान किए गए।

विधिक सुधार

मार्च 2012 के अंत तक 21 राज्यों ने अपने संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी एक्ट में संशोधन किया था। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और असम सरकार ने सहकारी समितियों से संबंधित अपने एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की है, वास्तविक संशोधन अभी लंबित है और इसमें कुछ और समय लगेगा। पंजाब और उत्तराखंड में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित एक्ट में संशोधन संबंधित राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

विधायी सुधारों का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को संपूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (क) जमाकर्ताओं सहित वित्तीय सेवाओं के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्ण मताधिकार के साथ सदस्यता सुनिश्चित करना, (ख) सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में राज्यों के हस्तक्षेप को हटाना, (ग) मौजूदा बोर्डों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले समय पर चुनाव सुनिश्चित करना, और (घ) राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित करना ताकि वे निर्वाचित बोर्डों का अधिलंघन न कर सकें।

प्रशिक्षण में सुधार

निदेशक-मंडल के सदस्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के अलावा सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए नाबार्ड ने नौ प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं। ये कार्यक्रम नाबार्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा राज्यों के प्रशिक्षण भागीदारों और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के साथ मिलकर आयोजित किये जा रहे हैं।

कंपनी अभिशासन में सुधार

रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पेशेवर निदेशकों की नियुक्ति के लिए फ़िट एंड प्रॉपर मानदंड निर्धारित किए हैं। इन सुधारों के अनुसरण में सभी सहकारी बैंक इन मानदंडों को लागू कर रहे हैं।

प्रौद्योगिकीय सुधार

नाबार्ड ने कोर सॉफ्टवेयर को अंतिम रूप दिया है और इसे 20 राज्यों को उपलब्ध कराया गया है, जो इस प्रकार हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू ऐण्ड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 10 राज्यों में सॉफ्टवेयर का परीक्षण पूरा कर लिया गया है, जो इस प्रकार हैं- असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। साथ ही कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा में परीक्षण कार्य प्रगति पर है। शेष राज्यों ने इसे परीक्षण स्तर पर चलाने का कार्य आरम्भ कर दिया है।

5.59 इस कार्य योजना को अंतिम रूप देने के बाद 25 राज्यों ने इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार एवं नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं जिनका देश की अल्पकालिक सहकारी संस्थाओं में 96 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है।

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना का पुनरुद्धार पैकेज प्रतीक्षित है

5.60 अल्पकालिक सहकारी संरचना के मामले की तरह ही दीर्घावधि के सहकारी समितियों में लागू किये जाने योग्य सुधार के लिए कार्य योजना पर सुझाव देने के लिए 2005 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं (दीर्घावधि) के पुनरुद्धार के बारे में एक टास्क फोर्स (अध्यक्ष: प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन) का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने अक्तूबर 2007, जनवरी 2008 और फरवरी 2008 में विशेष रूप से बुलाई गई तीन बैठकों में राज्य सरकारों के साथ टास्क फोर्स की सिफारिशों पर चर्चा की। केंद्रीय बजट 2008-09 में यह संकेत दिया गया था कि लंबी अवधि की सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना लागू किये जाने पर राज्य सरकारों के साथ आम सहमति बन पाई थी।

5.61 कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना लागू किये जाने और राज्य सरकारों से प्रतिसूचना प्राप्त होने के बाद केन्द्र सरकार ने दीर्घावधि सहकारी समितियों के लिए सुधार पैकेज को संशोधित किया।

हालांकि पैकेज की घोषणा से पहले केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित पृष्ठभूमि को देखते हुए दीर्घावधि सहकारी समितियों के लिए एक अलग पैकेज की व्यवहार्यता और प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है: (i) अल्पावधिक सहकारी समितियों के लिए एक पैकेज का कार्यान्वयन और (ii) वित्तीय समावेशन नीति के कारण हाल के वर्षों में वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से शाखा और व्यापार विस्तार।

5.62 इसके परिणामस्वरूप, सितम्बर 2009 में एक अलग टास्क फोर्स (अध्यक्ष: श्री जी.सी. चतुर्वेदी) का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। अतः दीर्घावधि सहकारी समितियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सुधार पैकेज की घोषणा प्रतीक्षित है।

6. सहकारी संस्थाओं पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाले ग्रामीण ऋण संबंधी उपायों से संबंधित प्रगति

किसान क्रेडिट कार्ड

5.63 किसानों को पर्याप्त, समय पर और सस्ते ऋण मुहैया कराने के लिए सहकारी समितियों, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में वाणिज्य बैंक अग्रणी हैं

5.64 मार्च 2012 के अंत तक जारी किए गए कुल किसान क्रेडिट कार्डों में वाणिज्य बैंकों का स्थान 58 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अग्रणी रहा। इसमें जारी कुल कार्डों में सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भागीदारी शेष 17 प्रतिशत रही है (परिशिष्ट सारणी V.9 के साथ पठित चार्ट V.28)।

5.65 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू किये जाने के बाद से ही जारी किए गए कार्डों की कुल संख्या में वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि देखी गई है जबकि सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी में कमी पाई गई है (चार्ट V.28)। हालांकि 2008-09 के बाद से सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में सुधार आया है फिर भी किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में वाणिज्य बैंक देश में सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम बने हुए हैं।

चार्ट V.28 : जारी किए गए कुल किसान क्रेडिट कार्डों में ग्रामीण ऋण संस्थाओं की हिस्सेदारी

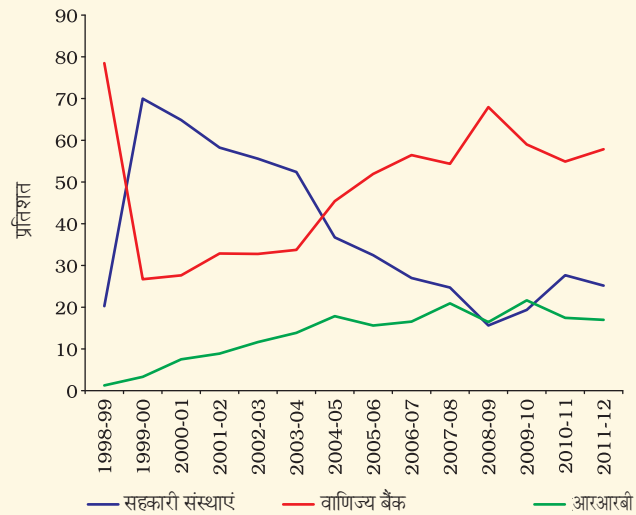

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई गणना।

किसान क्रेडिट कार्ड सामान्य रूप से कृषि ऋण और विशेष रूप से वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जा रहे कृषि ऋण के लिए वाहक के रूप में उभर रहे हैं

5.66 कृषि ऋण प्रदान करने वाली तीनों संस्थाओं अर्थात सहकारी संस्थाओं, वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच उनके द्वारा जारी किये गए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या तथा प्रत्यक्ष कृषि ऋण के लिए दी गई राशि में हिस्सेदारी के आधार पर तुलना से एक समान प्रवृत्ति उजागर होती है (चार्ट V.29 के साथ पठित चार्ट V.28)।

चार्ट V.29 : प्रत्यक्ष कृषि ऋण में ग्रामीण ऋण संस्थाओं की हिस्सेदारी

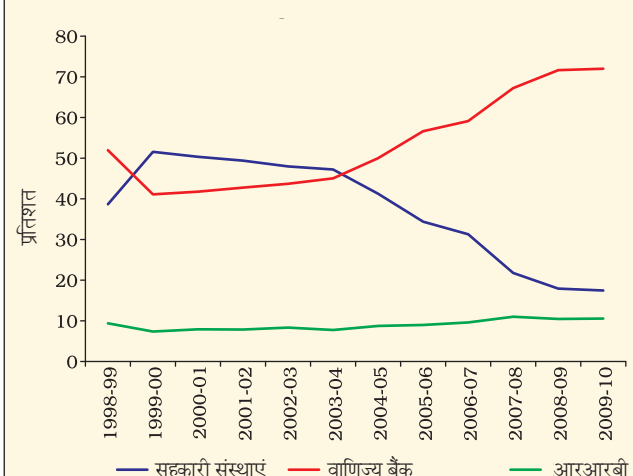

टिप्पणी: उपलब्ध आंकड़ों के अभाव में प्रत्यक्ष कृषि ऋण की शृंखला 2009-10 में टूट जाती है।

स्रोत: हैंडबुक ऑन इंडियन इकोनोमी के विभिन्न अंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई गणना

5.67 2000 के दशक में भारत में कुल और प्रत्यक्ष कृषि ऋण में तीव्र वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्य बैंकों के साथ जुड़ी हुई थी और वाणिज्य बैंक सहकारी संस्थाओं से आगे निकलकर देश में कृषि ऋण के सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2000 के दशक में जारी किये गए किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या में वाणिज्य बैंकों की हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि देखी गई। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड ने कुछ मायनों में देश में कृषि ऋण में वृद्धि करने और 2000 के दशक में कृषि ऋण में वाणिज्य बैंकों की हिस्सेदारी को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

7. समग्र मूल्यांकन

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र अधिक लाभप्रद, सुदृढ़ और विकासशील है लेकिन पूँजी पर्याप्तता संबंधी चिंताओं से ग्रस्त है

5.68 2005 में किए गए नियामक सुधारों के बाद से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों ने उल्लेखनीय प्रसार करके एक नई गाथा प्रस्तुत की है। हाल के दिनों में हुए सुधारों के अनुसार इस क्षेत्र में 2011-12 में भी लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ आस्ति में द्वि-अंकीय बढ़ोतरी हुई है। समेकन के फलस्वरूप मजबूत संस्थाओं में विकास हुआ है लेकिन इस क्षेत्र से कमजोर संस्थाएं बाहर हो गई हैं। साथ-साथ इस क्षेत्र में आस्ति संकेन्द्रण की सीमा में भी वृद्धि हुई है। इसके नकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें तो हालांकि शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता का स्तर समग्र रूप से संतोषजनक था पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी की स्थिति बहुत कमजोर दिखी। कुछ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों ने आरक्षित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात ऋणात्मक होने की सूचना दी है।

शीर्ष स्तरों पर पुनरुद्धार की संभावना वाली आर्थिक दृष्टि से कमजोर अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

5.69 ग्रामीण सहकारी समितियों के अंतर्गत, अल्पावधि की शीर्ष स्तर की ग्रामीण सहकारी समितियों में हाल की अवधि के अनुरूप 2010-11 में लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता के मामले में पुनरुद्धार के कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं जिसका आंशिक कारण इस क्षेत्र में किये जा रहे सुधार हो सकते हैं। यद्यपि 2010-11 में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलन पत्र के आकारों में कमी रही थी फिर भी इन संस्थाओं के समग्र लाभ में वृद्धि और इनकी अनर्जक आस्तियों के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में सुधार सामान्यरूप से सभी क्षेत्रों में हुए हालांकि पश्चिमी क्षेत्र इसका प्रमुख अपवाद रहा।

5.70 जहाँ एक ओर सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, वहीं निम्नतर टियर की जांच किए जाने पर वित्तीय स्थिति कमजोर होती जा रही है। राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति से बेहतर थी और प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी की वित्तीय स्थिति की तुलना में बेहतर थी। इस प्रकार वह प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी जिस पर बहुत अधिक कर्ज है और जो बहुत नुकसान में है, अभी भी अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में सबसे कमजोर है।

दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति कमज़ोर बनी रही

5.71 अल्पावधि सहकारी ग्रामीण संस्थाओं के विपरीत दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में नुकसान पहले की ही तरह 2010-11 में भी जारी रहा और आस्ति गुणवत्ता भी कमजोर बनी रही। हाल की अवधि के अनुरूप 2010-11 में राज्य और प्राथमिक कृषि सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों की आस्तियों के आकार में वृद्धि अल्पावधि संस्थाओं की तुलना में काफी कम रही है। इससे ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की कुल आस्ति में दीर्घावधि सहकारी समितियों की हिस्सेदारी क्रमिक रूप से कम हो गई।

5.72 संक्षेप में, शहरी सहकारी और अल्पावधि ग्रामीण सहकारी क्षेत्रों से संबंधित सुधारों से इनमें पुनरुद्धार की प्रक्रिया शुरू हो गई प्रतीत होती है। शहरी सहकारी क्षेत्र में अब वित्तीय निष्पादन में सुधार दिखाई देने लगा है और वित्तीय स्थिति अच्छी हुई है लेकिन अल्पावधि ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में पुनरुद्धार अधिक नाजुक है और अभी भी इसे देश के सभी क्षेत्रों में और क्षेत्र के सभी टियरों में फैलाना शेष है। आने वाले वर्षों में यह देखना होगा कि क्या यह पुनरुद्धार निरंतर और व्यापक बना रहेगा। इसके अलावा, यह जरूरी है कि भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण में दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं द्वारा निभाई जा रही महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए।